घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 264- शनिवार 25- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संक्षिप्त समाचार

नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा-लगातार गलतियों के सिलसिले को खत्म करे सरकार

नई दिल्ली,24 जुलाई 2026। नीट पेपर लीक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार गलतियों का सिलसिला इसी तरह जारी नहीं रह सकता। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र से कहा कि वे इस मामले पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। पीठ ने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार से नीट-यूजी परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर-आधारित परीक्षा की ओर बढने की योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी। पीठ ने कहा,अगर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है तो डेटा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। कृपया हमें बताएं कि आप पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जाने के लिए क्या कर रहे हैं। कृपया बताएं कि कंप्यूटर-आधारित परीक्षा में जाने पर आप डेटा की सुरक्षा कैसे करेंगे। सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,प्रिंटिंग से लेकर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया कोर्ट के सामने रखी जाएगी। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है और कंप्यूटर-आधारित परीक्षाओं,डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी एक हलफनामे में दी जाएगी।

रवनीत बिट्टू का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर किया

लुधियाना,24 जुलाई 2026। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को 24 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। बिट्टू को कुछ समय पहले भाजपा ने राज्यसभा की टिकट नहीं दी थी,जिस वजह से वे अब सांसद नहीं थे। वे केंद्र सरकार में पंजाब से बीजेपी के इकलौते राज्य मंत्री थे, उन्हें रेल राज्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग दिया गया था। वह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं। अब बिट्टू अगले साल होने वाला पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। रवनीत बिट्टू ने लुधियाना से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था,लेकिन वह हार गए थे। इसके बाद भाजपा ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनाया। इसके बाद 21 जून को कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद भाजपा ने उनकी जगह अमृतसर से भाजपा नेता तरुण चुघ को राज्यसभा भेज दिया। हालांकि नियमों के मुताबिक बिट्टू बिना सांसद बने भी 6 महीने यानी 21 दिसंबर तक मंत्री बने रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे को लेकर रवनीत बिट्टू ने कहा...मैंने 2-3 महीने पहले ही इस बारे में रिक्वेस्ट की थी। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर आए थे,उस दिन भी मैंने ये बात कही। पिछले सेशन में भी मैं शामिल नहीं हुआ था।

बहार के नवादा में आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत,दो महिलाएं झुलसीं

नवादा,24 जुलाई 2026। बिहार के नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड अंतर्गत सांगोवर गांव में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। घायलों का इलाज नारदीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतकों में तीन किसान और एक 12 वर्षीय बालक शामिल हैं। सभी लोग खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए खेत में काम कर रहे लोग पास के एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल नारदीगंज पीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा गया है।

पेपर लीक पर कड़ी सजा वाले बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

10 साल की जेल,1 करोड़ जुर्माना

नई दिल्ली,24 जुलाई 2026। पेपर लीक विवाद और छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। इसमें पेपर लीक से जुड़े संशोधित विधेयक पर चर्चा हुई और इसे मंजूरी भी दे दी गई।

संसद के इसी मानसून सत्र के दौरान विधेयक को अगले हफ्ते पेश किया जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान किए जाने के संकेत दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक,प्रस्तावित विधेयक में पेपर लीक में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को 3 से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, संगठित पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है। साथ ही इन मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, जो 3 महीने के भीतर फैसला सुनाएगी। दरअसल, पीएम मोदी ने गुरुवार रात एक वीडियो जारी करके कहा था कि पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा होगी, फिर से संसद में पेश किया जाएगा। पीएम ने कहा...पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक,पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है,वे जेल में हैं।

अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता बिल

बताया जाता है कि संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद सभी की नजर अगले हफ्ते संसद पर रहेगी, जहां इस अहम विधेयक को पेश किए जाने की संभावना है। केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी किया। सरकार ने 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने विनीत जोशी की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है।

केंद्र ने कर्नाटक-आंध्र प्रदेश में रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली,24 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने शुक्रवार को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी-गुंटाकल सेक्शन पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,264 करोड़ रुपये है और इसे वर्ष 2028-29 तक पूरा किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह परियोजना पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। परियोजना से भारतीय रेल नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की वृद्धि होगी और तीन जिलों के करीब 99 गांवों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। इन गांवों की आबादी लगभग सात लाख है। इस परियोजना से लौह अयस्क,डोलोमाइट,चूना पत्थर, इस्पात, कोयला,खाद और खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के परिवहन की क्षमता बढ़ेगी। अनुमान है कि अतिरिक्त माल यातायात 16.22 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ेगा। परियोजना से तेल आयात में 1.32 करोड़ लीटर की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में 6.67 करोड़ किलो की कमी आएगी, जो 0.27 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। परियोजना से बल्लारी किला और श्री कुमार स्वामी मंदिर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क भी बेहतर होगा।

सरकार के साथ वार्ता के बाद सीजेपी बोली... प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं

नई दिल्ली,24 जुलाई 2026। सरकार के साथ यहां कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमारी इस मांग पर सरकार ने शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह शामिल थे, जबकि सीजेपी का प्रतिनिधित्व आशुतोष रांका और सौरव दास ने किया। आशुतोष रांका ने पत्रकारों को बताया,सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी। सरकार ने छात्रों पर एफआईआर और कानूनी मामले वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को गैर-समझौतावादी बताते हुए स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी ने कहा कि जब तक उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं होती,तब तक जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहेगा। सीजेपी और सरकार के बीच दिल्ली में यह दूसरे दौर की बातचीत थी। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। उस बैठक में भी सीजेपी की ओर से आशुतोष रांका और सौरव दास मौजूद रहे थे। इसके पहले सरकार ने कहा था कि हमने चार बार सीजेपी को बातचीत के लिए बुलाया पर वे नहीं आए। वहीं, सीजेपी ने कहा था कि उसके प्रतिनिधि बात करने के लिए जेपी नड्डा के आवास पर नहीं जाएंगे, किसी तटस्थ स्थान पर बातचीत हो सकती है।

धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री,इस्तीफा दें : राहुल

उनकी वजह से हजारों लोग सड़क पर,पैलेट गन से घायल छात्र की टी-शर्ट उठाकर घाव दिखाए

नई दिल्ली,24 जुलाई 2026। राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने आवास 10 जनपथ पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। वे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग सड़कों पर हैं।' उन्होंने छात्र के हाथ में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने कहा, 'मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था, जब वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन कर रहा था।' उन्होंने कहा, 'सरकार का कहना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसकी आंख को नुकसान पहुंचा है और उसकी देखने की क्षमता चली गई है।'

साहिल की रोशनी लौटने की सिर्फ 1% संभावना

राहुल ने जिस छात्र की चोट दिखाई। उसका नाम साहिल लोचाब है। वह 19 साल का है और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की पैलेट गन से इनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। AIIMS के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में सर्जरी हुई है। परिवार के मुताबिक, डॉक्टरों ने बताया है कि घायल आंख की रोशनी लौटने की सिर्फ 1% संभावना है, क्योंकि आंख की पुतली को गंभीर नुकसान पहुंचा है। साहिल दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हैं। उनकी मां ज्योति ने बताया, 'वह पहले भी CJP के प्रदर्शन में गया था।

राहुल बोले...प्रधान के इस्तीफे तक कोई चर्चा नहीं करेंगे

राहुल गांधी ने कहा,जब तक प्रधान को हटाया नहीं जाता,हम कोई बातचीत या चर्चा नहीं करेंगे। रिजिजू ने बयान दिया कि वह हमारे सांसदों को बताना चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। सामान्य नियम यह है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है, तो उसका जवाब दिया जाता है। जब मैं जवाब देना चाहता था,तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। मुझे मौका नहीं दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा,मैंने आज एक बार फिर केसी वेणुगोपाल जी से अनुरोध किया है, क्योंकि हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि नीट पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और चर्चा की मांग की है।

राज्यसभा में राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समान दर्जा देने वाला विधेयक पेश,संसद के दोनों सदन सोमवार तक स्थगित

नई दिल्ली,24 जुलाई 2026। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने शुक्रवार को राज्यसभा में राष्ट्रगीत 'वंदेमातरम' को राष्ट्रगान के समान दर्जा दिलाने वाले वाला विधेयक पेश किया। नित्यानंद राय ने सदन में आरोप लगाया कि विपक्ष विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को भी सम्मान प्राप्त होगा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों का समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में शुक्रवार को भी विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज प्रभावित रहा। लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही की शुरुआत में करगिल दिवस (26 जुलाई) पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई । इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे और बाद में सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरी ओर राज्यसभा में पहले कार्यवाही 12 बजे, फिर 02 बजे और फिर सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में दोपहर 2 बजे कार्यवाही प्रारंभ होने पर नित्यानंद राय ने सदन में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन किए जाने वाला विधेयक पेश किया। विधेयक को पेश किये जाने का सीपीआई नेता संदोष कुमार पी और सीपीआई (एम) नेता जॉन ब्रिटास ने विरोध किया। ब्रिटास ने कहा कि संसद साधारण कानून बनाकर संविधान की मूल व्यवस्था को नहीं बदल सकती। संविधान सभा ने लगभग तीन वर्षों के गहन विचार-विमर्श के बाद जानबूझकर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को समान संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। यदि संविधान निर्माताओं की ऐसी मंशा होती तो वे इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करते। उन्होंने कहा कि कानून के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रवाद को गढ़ा नहीं जा सकता। इस विधेयक का उद्देश्य समाज का ध्रुवीकरण करना प्रतीत होता है। संदोष कुमार ने कहा कि भारतीयों को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। रवींद्रनाथ ठाकुर सहित भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इसे समझा था। यही कारण है कि राष्ट्रगान के केवल दो अंतरों को ही अपनाया गया। वे इस विधेयक का विरोध करते हैं कि इसके माध्यम से रवींद्रनाथ ठाकुर और बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के बीच कृत्रिम विभाजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच लोकसभा में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर विपक्ष से छात्रों के मुद्दे पर चर्चा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया है और समाजिक कार्यकर्ता (सोनम वांगचुक) ने भी भूख हड़ताल समाप्त कर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को इस विषय में समझायें। इससे पहले सुबह 26 जुलाई को रविवार होने के कारण करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है।

यह सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह किए बिना अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया तथा अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। वहीं, राज्यसभा में भी करगिल शहीदों को नमन किया गया।

यूएई से भारत लाया गया 100 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश ठगी का आरोपित अविनाश अर्जुन राठौड़ इतिहास

नई दिल्ली,24 जुलाई 2026। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से रेड नोटिस जारी आरोपित अविनाश अर्जुन राठौड़ को भारत प्रत्यर्पित (डिपोर्ट) कराया। निवेशकों से निश्चित मासिक रिटर्न का झांसा देकर बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के मामले में वांछित राठौड़ को गुरुवार को मुंबई लाया गया,जहां महाराष्ट्र पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने शुक्रवार को बताया कि एजेंसी ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के समन्वय से से अविनाश अर्जुन राठौड़ को भारत प्रत्यर्पित किया। उसने अपने अन्य साथियों के साथ आपराधिक साजिश के तहत निवेशकों को विभिन्न निवेश योजनाओं में निश्चित मासिक रिटर्न का झूठा आश्वासन देकर निवेश करने के लिए प्रेरित करता था। इसके बाद उसने निवेशकों की राशि का कथित रूप से गबन कर लिया और धन को विभिन्न बैंक खातों तथा डीमैट खातों के माध्यम से इधर-उधर स्थानांतरित कर दिया।

हिमाचल में पहाड़ी से गिरी चट्टान की चपेट में आई टाटा सुमो,13 लोगों की मौत

शिमला,24 जुलाई 2026। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में शुक्रवार को एक सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। उदयपुर थाना क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की मुख्य सड़क पर कढ़ूनाला-राहौली के पास पहाड़ी से अचानक गिरी भारी चट्टान की चपेट में एक टाटा सुमो आ गई। हादसे में वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हो गई,जबकि दो लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को बचाकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के बाद पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। पुलिस के अनुसार, टाटा सुमो (एचपी-01एम-2210) में चालक सहित कुल 15 लोग सवार थे। वाहन को बीर सिंह चला रहे थे। कढ़ूनाला क्षेत्र में राहौली के पास पहुंचते ही पहाड़ी से अचानक बड़ी चट्टान नीचे आ गिरी। वाहन सीधे उसकी चपेट में आ गया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही अधिकांश यात्रियों की मौत हो गई। चट्टान गिरने से वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। लाहौल स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि हादसे में वाहन में सवार 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि दो लोग घायल हैं और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि हादसा चंबा जिले के पांगी और लाहौल स्पीति जिले के सीमावर्ती इलाके में हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी मृतक चंबा जिले के पांगी क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि जिला लाहौल की पुलिस चौकी तिंदी और उदयपुर थाना पुलिस मौके पर मौजूद है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। मृतकों की पहचान की जा रही है। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उन्हें परिजनों को सौंपा जाएगा। यह हादसा ऐसे समय हुआ है, जब प्रदेश में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में बड़ी कार्रवाई...47 अधिकारी-कर्मचारी को बर्खास्त किया

नई दिल्ली,24 जुलाई 2026। राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षाओं के संचालन को लेकर लगातार विवादों के बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार,हटाए गए कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। नीट सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह कार्रवाई की गई है। पिछले कई महीनों से देशभर में लाखों छात्र और विभिन्न छात्र संगठन परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह कदम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में व्यापक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी,सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए एजेंसी के ढांचे और कार्यप्रणाली में बड़े स्तर पर बदलाव करने की तैयारी में है। आने वाले समय में कई अन्य सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे। हालांकि, सरकार की ओर से यह संकेत भी दिए गए हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे और उनके इस्तीफे का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इस कानून को शीघ्र संसद से पारित कराकर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि नीट प्रश्नपत्र लीक मामले के कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उन्हें न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। वर्ष 2018 से अब तक एजेंसी देशभर में 270 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं का आयोजन कर चुकी है, जिनमें लगभग 6 करोड़ 60 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 में अब तक एजेंसी 12 परीक्षाओं का आयोजन कर चुकी है, जिनमें करीब 65 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में 39 स्थायी पद स्वीकृत हैं,जिनमें से वर्तमान में केवल 24 पदों पर नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं,जबकि 15 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त एजेंसी में 73 कर्मचारी संविदा पर तथा 124 कर्मचारी बाह्य स्रोत (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से कार्यरत हैं। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक सुधार,कड़े कानून और जवाबदेही तय करने जैसे उपायों से राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में छात्रों का विश्वास पुनः स्थापित किया जा सकेगा।

संपादकीय

पर्यावरण के लिए चुनौती बनी एआई

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज आधुनिक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती तकनीक में से एक है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि,उद्योग,अंतरिक्ष, रक्षा और संचार से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक इसका उपयोग बढ़ रहा है। चैटबाट,एआई सर्च,तस्वीर और वीडियो बनाने वाली तकनीक अब हमारी डिजिटल जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं,लेकिन एआई के विकास का एक पर्यावरणीय पक्ष भी है,जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आम लोगों को लगता है कि एआई केवल मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करता है,लेकिन इसके पीछे बड़े-बड़े डाटा सेंटरों में हजारों शक्तिशाली सर्वर लगातार चलते रहते हैं।

एआई माडल को प्रशिक्षित करने और उपयोगकर्ताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत अधिक कंप्यूटिंग शक्ति चाहिए। इससे सर्वर गर्म होते हैं और उन्हें ठंडा रखने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा और कुछ मामलों में पानी की भी जरूरत पड़ती है। दुनिया पहले ही जलवायु परिवर्तन,अनियमित वर्षा, बढ़ती आबादी और तेज शहरीकरण के कारण जल संकट का सामना कर रही है। ऐसे में डाटा सेंटरों की बढ़ती जल आवश्यकता नई चिंता पैदा कर रही है। इसलिए एआई के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन जरूरी है।

भविष्य में ऐसी तकनीक और डाटा सेंटर विकसित करने होंगे,जो कम पानी और ऊर्जा का उपयोग करें। यह समझना जरूरी है कि एआई स्वयं पानी का इस्तेमाल नहीं करता। पानी की खपत मुख्य रूप से उन डाटा सेंटरों में होती है, जहां एआई सेवाओं को चलाने वाले हजारों सर्वर और शक्तिशाली ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू लगातार काम करते हैं। एआई माडल की ट्रेनिंग और संचालन के दौरान ये मशीनें बहुत गर्म हो जाती हैं। उन्हें ठंडा रखने के लिए अलग-अलग कूलिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है,जिनमें कुछ प्रणालियां पानी पर आधारित होती हैं। वाष्पीकरणीय कूलिंग में पानी गर्मी को सोखकर भाप के रूप में वातावरण में चला जाता है। इस कारण इस्तेमाल किया गया पानी पूरी तरह वापस उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे-जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा,वैसे-वैसे डाटा सेंटरों में कंप्यूटिंग और सर्वरों की संख्या भी बढ़ सकती है। इससे गर्मी को नियंत्रित करने के लिए अधिक ऊर्जा और कुछ परिस्थितियों में अधिक पानी की जरूरत होगी।

एआई का वाटर फुटप्रिंट केवल डाटा सेंटरों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे ऊर्जा उत्पादन की भी बड़ी भूमिका है। एआई माडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। दुनिया के कई हिस्सों में बिजली उत्पादन अभी भी कोयला और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। थर्मल पावर प्लांटों में बिजली उत्पादन और कूलिंग प्रक्रियाओं के लिए पानी की जरूरत होती है। इस प्रकार एआई के लिए इस्तेमाल की गई बिजली का एक हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से जल संसाधनों पर भी दबाव डाल सकता है।

यही कारण है कि एआई के पर्यावरणीय प्रभाव को समझते समय केवल डाटा सेंटर के भीतर इस्तेमाल होने वाले पानी को देखना पर्याप्त नहीं है। बिजली उत्पादन,चिप निर्माण, सर्वर निर्माण सहित पूरी आपूर्ति शृंखला में प्रयोग हुए वाटर फुटप्रिंट को भी ध्यान में रखना होगा। इस दृष्टि से एआई का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट एक बहुस्तरीय समस्या है-जल,ऊर्जा,कार्बन उत्सर्जन और इलेक्ट्रानिक कचरे के रूप में इसके कई आयाम हैं और जैसे-जैसे जेनरेटिव एआई और लार्ज लैंग्वेज माडल का विस्तार हो रहा है,यह प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु पर भारी दबाव डाल रहा है।

बड़ी टेक कंपनियां भी अब इस चुनौती को पहचानने लगी हैं। कई कंपनियां जल संरक्षण,जल पुनर्भरण की दिशा में काम करने का दावा कर रही हैं। वर्षा जल संचयन,अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और अधिक कुशल कूलिंग तकनीकें इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे डाटा सेंटरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो पुनर्चक्रित या गैर-पेयजल का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन कंपनियों के वादे पर्याप्त नहीं हैं। जरूरत पारदर्शिता की है। हर बड़े डाटा सेंटर को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि वह प्रतिदिन कितना पानी इस्तेमाल करता है,पानी का स्रोत क्या है,कितना पानी पुनर्चक्रित किया जाता है और स्थानीय जल संसाधनों पर उसका प्रभाव कितना है। सरकारों को भी डाटा सेंटरों की स्थापना के लिए स्पष्ट पर्यावरणीय मानक तय करने चाहिए।

निःसंदेह एआई मानव सभ्यता की सबसे शक्तिशाली तकनीक में से एक बन गई है,लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि इसके विकास का पर्यावरण पर कितना असर पड़ रहा है। चूंकि हर डिजिटल गतिविधि के पीछे ऊर्जा,पानी और अन्य संसाधनों की जरूरत होती है और एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डाटा सेंटरों की संख्या और उनकी ऊर्जा तथा पानी की मांग भी बढ़ रही है। इसलिए अब एआई को केवल तकनीकी चमत्कार के रूप में देखने के बजाय उसके पर्यावरणीय प्रभाव पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। जरूरत ऐसी जिम्मेदार और टिकाऊ तकनीक की है,जो कम ऊर्जा और पानी में अधिक काम करे तथा अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाए। डिजिटल विकास तभी सार्थक होगा,जब वह मानव जीवन को बेहतर बनाने के साथ पृथ्वी और उसके सीमित संसाधनों की भी रक्षा करे।

एक देह का विदा होना,कई घरों में सूर्योदय बन सकता है...

*** जिसे हम शव कहते हैं,वह किसी का जीवन बन सकता है**
*** जब व्यवस्था संवेदनशील होती है,तब मृत्यु भी जीवन बाँटती है...**

रितेश कुमार जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

प्रतीकात्मक: दैनिक घटती-घटना

जीवन का सबसे कठिन संघर्ष अक्सर अस्पताल की चारदीवारी के भीतर लिखा जाता है,जहाँ हर साँस उम्मीद और समय के बीच अंतिम संवाद बन जाती है। कहीं माँ की प्रार्थनाएँ बेटे की धड़कनों का सहारा हैं,कहीं पिता की आँखें बेटी के लिए एक अंग की प्रतीक्षा में हैं,तो कहीं एक मासूम अनजान है कि उसका कल किसी अजनबी के निर्णय पर टिका है। विज्ञान ने एक देह से कई जीवनों को फिर धड़काने की शक्ति पा ली है,लेकिन संवेदनहीन व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इसलिए भारत में अंगदान केवल चिकित्सा नहीं, हमारी सामूहिक मानवता की परीक्षा है। जब तक यह संवेदना सशक्त नीतियों में नहीं उतरती,तब तक प्रतीक्षा सूची का हर नाम किसी मरीज का नहीं,बल्कि अधूरी ज़िंदगी की मौन पुकार बना रहेगा।

संवेदनशील समाज केवल उपदेश नहीं देता,बल्कि करुणा को व्यवस्था का आधार बनाता है। अमेरिका के मिशिगन राज्य ने इसे कानून का रूप दिया है। वहाँ जीवित अंगदाता बनने वाले कर्मचारी के लिए नियोक्ता को 12 सप्ताह के वेतन के बराबर टैक्स क्रेडिट मिलता है। यह केवल आर्थिक प्रोत्साहन नहीं,बल्कि जीवन बचाने के निर्णय का सम्मान है। इससे कर्मचारी को न नौकरी खोने का डर रहता है,न आय घटने की चिंता,और नियोक्ता भी बिना अतिरिक्त बोझ के उसका साथ दे सकता है। भारत में निजी क्षेत्र के अनेक कर्मचारी इच्छा होने पर भी आर्थिक असुरक्षा के कारण अंगदान का साहस नहीं जुटा पाते। ऐसे में यह मॉडल संवेदना और व्यवस्था का प्रभावी उदाहरण बन सकता है।

भारत की सबसे बड़ी कमी अंगदान की इच्छा नहीं,बल्कि उसे संभव बनाने वाली व्यवस्था है। अधिकांश प्रत्यारोपण आज भी जीवित रिश्तेदारों के दान पर निर्भर हैं,जबकि मृतक अंगदान की दर प्रति मिलियन आबादी पर एक से भी कम है। हर वर्ष लगभग 1.6 लाख सड़क दुर्घटना मौतों के बावजूद केवल 1,000-1,200 मृतक अंगदान हो पाते हैं। इसके विपरीत,स्पेन ने यह दर 48 प्रति मिलियन तक पहुँचा दी है। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (नॉटो) के अनुसार 2025 में लगभग 20 हजार प्रत्यारोपण हुए, जबकि आवश्यकता इससे कहीं अधिक है। हर वर्ष लाखों लोग अंगों की प्रतीक्षा में दम तोड़ देते हैं। यह केवल चिकित्सा व्यवस्था की विफलता नहीं,बल्कि अंगदान को राष्ट्रीय सामाजिक संपदा न मानने वाली नीतिगत सोच का परिणाम है। जहाँ लोग अंगों के अभाव में मरें,वहाँ संकट संसाधनों का नहीं,दृष्टिकोण का होता है।

किसी अनजान को जीवन देने का साहस तभी जन्म लेता है,जब व्यवस्था सुरक्षा का विश्वास दे। भारत में अंगदान की सबसे बड़ी बाधा चिकित्सा नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिकअसुरक्षा है। परिवार की हिचक,उपचार का खर्च, लंबी रिकवरी और नौकरी का भय लोगों को पीछे हटा देता है। मिशिगन मॉडल इसी समस्या का समाधान देता है। यदि भारत में भी कंपनियों को कर प्रोत्साहन मिले,तो वे कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दे सकेंगी। आज 82 हजार से अधिक लोग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में हैं, जबकि एक मृतक अंगदाता आठ से दस जीवन बचा सकता है। कई बार एक संवेदनशील नीति,हजारों अपीलों से अधिक जीवन बचा देती है।

यदि भारत इस दिशा में निर्णायक पहल करे,तो उसका प्रभाव केवल प्रत्यारोपण तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व की परिभाषा भी बदलेगी। अस्पताल बनाना और उपकरण दान करना महत्वपूर्ण है,पर अब अपने कर्मचारियों की जीवनदायी संवेदना को संरक्षण देना भी आवश्यक है। मिशिगन की तर्ज पर कर प्रोत्साहन मिलने पर कंपनियाँ सवेतन अवकाश के साथ उपचार,रिकवरी और पुनर्वास में सहयोग दे सकेंगी। यह ऐसा निवेश होगा,जिसका प्रतिफल बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि बची हुई धड़कनों और लौटी मुस्कानों में दिखाई देगा। इसके साथ नॉटो और राज्य स्तरीय अंगदान नेटवर्क का विस्तार भी आवश्यक है, ताकि दान और प्रत्यारोपण के बीच समय की दूरी घट सके।

भारत के कुछ राज्यों ने साबित किया है कि अंगदान की दिशा संसाधनों से नहीं, संकल्प और सुदृढ़ व्यवस्था से बदलती है। तमिलनाडु,कर्नाटक और तेलंगाना इसके उदाहरण हैं, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्य अब भी पीछे हैं। मध्य प्रदेश सरकार दानकर्ताओं को 'गॉड ऑफ ऑनर' का सम्मान देकर उन्हें समाज का हीरो बनाती है। यह अंतर सुविधाओं से अधिक नीतिगत प्राथमिकताओं का है। यदि केंद्र सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ समान राष्ट्रीय नीति लागू करे,तो यह असमानता सिमट सकती है। भरोसेमंद प्रत्यारोपण तंत्र न केवल लाखों जीवन बचाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल टूरिज्म का विश्वसनीय केंद्र भी बना सकता है।

स्थायी परिवर्तन तब जन्म लेते हैं,जब नीति, समाज और संस्थाएँ एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ती हैं। अंगदान भी इसका अपवाद नहीं है। सरकार नीतिगत संरक्षण दे,उद्योग जगत आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करे और स्वयंसेवी संस्थाएँ जनजागरण का दायित्व निभाएँ–यही साझेदारी इस अभियान को जनआंदोलन बना सकती है। भारत में 4.8 लाख से अधिक नागरिक मृत्यु के बाद अंगदान के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। यह प्रमाण है कि संवेदना का अभाव नहीं,बल्कि भरोसे की कमी है। जिस दिन हर दानकर्ता परिवार को सम्मान और सुरक्षा का विश्वास मिलेगा,उसी दिन यह संख्या कई गुना बढ़ सकती है।

आखिरकार प्रश्न केवल अंगदान का नहीं,बल्कि उस व्यवस्था का है जो करुणा को साहस में बदल सके। भारत में अंगदान अब केवल व्यक्तिगत सद्कर्म नहीं,बल्कि सार्वजनिक नीति और सामाजिक सहभागिता का विषय बनना चाहिए। मिशिगन का मॉडल बताता है कि नीतिगत संरक्षण मिलने पर संवेदना हजारों परिवारों के लिए आशा बन जाती है। प्रतीक्षा सूची का हर नाम केवल एक मरीज नहीं,बल्कि पूरे परिवार के अधूरे भविष्य का प्रतीक है। आवश्यकता केवल अंगदान बढ़ाने की नहीं,बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की है,जहाँ जीवन बचाने वाला व्यक्ति स्वयं असुरक्षा का शिकार न बने। जिस दिन यह विश्वास स्थापित होगा, अंगदान अभियान नहीं, भारत की मानवीय चेतना का स्वाभाविक संस्कार बन जाएगा।

बाब अल-मंडेब पर हूतियों के पहरे से संकट में वैश्विक व्यापार और भारत का व्यापार सुरक्षा कार्यबल

दुर्गेश्वर राय, गोरखपुर,उत्तरप्रदेश

यमन के हूती विद्रोहियों ने सोमवार, 20 जुलाई को एक चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने सऊदी अरब पर तत्काल प्रभाव से नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी है। हूती ईरान समर्थित एक सशस्त्र समूह है। साल 2014 से राजधानी सना और उत्तरी यमन पर इनका कब्जा है। उन्होंने इस नाकाबंदी को आंख के बदले आंख की कार्रवाई बताया है। उनका आरोप है कि सऊदी अरब ने 2015 में यमन के गृहयुद्ध में दखल दिया था। तब से यमन की घेराबंदी की गई। हूतियों ने इसे अन्यायपूर्ण और दमनकारी बताया। हूती इस नाकाबंदी को कैसे लागू करेंगे, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इनके 2023 और 2024 के बीच लाल सागर में जहाजरानी पर किये गए हमले से सीख लेने की जरुरत है।

इस पूरे संकट का केंद्र बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य है। अरबी भाषा में इसका अर्थ आंसुओं का द्वार होता है। यह एक संकीर्ण जलमार्ग है। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इसके एक तरफ यमन है। दूसरी तरफ अफ्रीका के हॉर्न में स्थित जिबूती और इरिट्रिया हैं। अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर यह केवल 29 किलोमीटर चौड़ा है। यह यूरोप के प्रवेश द्वार स्वेज नहर की ओर ले जाता है।

नाकाबंदी की यह घोषणा ऐसे समय आई है जब सऊदी अरब का दूसरा मुख्य समुद्री मार्ग भी बंद है। होर्मुज जलडमरूमध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है। फरवरी के अंत में अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा था। युद्ध जैसी स्थिति के बाद से यह मार्ग प्रभावी रूप से बंद है। तब से सऊदी अरब अपना तेल एशिया और अन्य स्थानों तक पहुँचाने के लिए ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का उपयोग कर रहा था। इसके जरिए तेल लाल सागर तक आता है और बाब अल-मंडेब से गुजरता है। अब इस मार्ग पर भी नाकाबंदी का खतरा मंडरा रहा है।

इस खतरे की जड़ें हाल के इतिहास में मौजूद हैं। अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू हुआ था। तब हूतियों ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाई। उन्होंने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक लाल सागर में कम से कम 40 जहाजों पर हमला किया। उनका दावा था कि जहाज इज़राइल से जुड़े थे। इसके जवाब में अमेरिका ने सहयोगियों के साथ कदम उठाया। उसने सिंगापुर और श्रीलंका के साथ मिलकर ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया। यह दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य लाल सागर में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। नवंबर 2023 और मार्च 2024 के बीच कम से कम 2,000 जहाजों ने स्वेज नहर का मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर लगाकर यात्रा की। वैश्विक शिपिंग मार्ग प्रभावी रूप से 170 साल पीछे चले गए। मिस्र ने स्वेज नहर का एक-चौथाई राजस्व खो दिया। जुलाई 2024 तक इज़राइल के लाल सागर स्थित इलात बंदरगाह को खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा।

भारत पर इसका सीधा असर पड़ा था। जहाजों के लंबा रास्ता तय करने से महत्वपूर्ण आयातों में देरी हुई। आयात बिल महंगा हो गया। आज स्थिति अधिक अप्रत्याशित है। क्षेत्र में अमेरिकी बलों का पूरा ध्यान ईरान पर केंद्रित है। यह स्पष्ट नहीं है कि वे लाल सागर को पहले की तरह सुरक्षित करेंगे या नहीं। अमेरिका की यह व्यस्तता खतरे को बढ़ाती है। इस मार्ग पर हजारों भारतीय नाविक काम करते हैं। इस प्रकार की कोई भी नाकाबंदी उनकी सुरक्षा और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

ऐसे में भारत मूकदर्शक नहीं बना रह सकता। 2024 में फ्रांस ने लेबनान में हिजबुल्लाह और इज़राइल के बीच मध्यस्थता के कारण अमेरिकी ऑपरेशन से दूरी बनाई थी। वे परिस्थितियां अब मौजूद नहीं हैं। फ्रांस और जापान को एशिया और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी के लिए लाल सागर की आवश्यकता है।

आर्टिकल 19 स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार और इतिहास रचता आंदोलन

केशी गुप्ता
द्वारका दिल्ली

भारत की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर युवाओं का आंदोलन आज ना सिर्फ देश भर में बल्कि अन्य देशों का हिस्सा भी बन गया है। इस आंदोलन का मकसद नीट पेपर लीक की जवाबदारी के आवाज में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तथा पेपर लीक की वजह से सुसाइड किए गए बच्चों के परिवार को दिये जाने वाले मुआवजे का है । जो कोई नाजायज़ मांग नहीं है । देश को एक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। 20 जुलाई 2026 शांतिपूर्ण संसद मार्च के दौरान युवाओं, लड़कियों को बर्बरता से पीटा गया। आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया । आंसू गैस छोड़ी गई । पुलिस कर्मियों की वर्दी पहने लोगों के साथ साथ बिना वर्दी के कथित शरारती तत्वों ने आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया । इसमें अनेकों युवा घायल तथा जख्मी हुए। जो संविधान में आधारित आर्टिकल 19 के विरुद्ध है। संविधान का आर्टिकल 19 किसे भी व्यक्ति,संगठन को शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन,अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है । इस मार्च के दौरान युवा लड़कियों के साथ बदसलुकी की गई,जिसके अनेको वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है । जो चीख चीख कर इस जुल्म के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं। आखिर क्यों एक शांत आंदोलन को मार पीट कर दबाने की कोशिश की गई ? वूमेन प्रोटेक्शन एक्ट को क्यों कर नजर अंदाज किया गया ? लोग इस आंदोलन का हिस्सा ना बन पाये इस दृष्टि से कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए है।

जिस देश में दिन रात विकास की बात की जाती है वहां क्यों युवाओं की सही मांग की सुनवाई नहीं हो रही? बड़ा सवाल ये है कि अगर देश का युवा पढ़ाई,कामकाज छोड़ कर सड़कों पर पीटता रहेगा तो देश का विकास कैसे होगा ? कथित मारपीट के खिलाफ डाली गई पिटिशन के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज का कथित बयान की रील वीडियो दिखा कर हमारा अपना समय बर्बाद न करें। एक सोई हुई व्यवस्था का प्रमाण है । आज जब देश का युवा समस्त देश को जगाने में लगा है, ऐसे में सरकार को उनके सुझावों और मांगों को सुन देश हित मे आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इतिहास तो हर कीमत पर रचा जाएगा गौर तलब बात ये है कि कौन किस तरह से याद किया जाएगा।

डॉक्टर बनने की राह में संवेदनाएँ कहाँ खो जाती हैं?

डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी, हरियाणा

देश में जब भी नीट परीक्षा होती है, उसके बाद केवल परिणामों की नहीं,बल्कि पूरी व्यवस्था की चर्चा शुरू हो जाती है। कभी पेपर लीक,कभी परीक्षा की पारदर्शिता, कभी आरक्षण, कभी कट-ऑफ और कभी लाखों विद्यार्थियों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव को लेकर बहस छिड़ जाती है। हर वर्ष करोड़ों सपनों का भार इस एक परीक्षा पर टिका होता है। माता-पिता अपनी वर्षों की बचत दाँव पर लगा देते हैं,विद्यार्थी दिन-रात एक कर देते हैं और समाज उन सफल अभ्यर्थियों को भविष्य का जीवनरक्षक मानकर गर्व महसूस करता है।

लेकिन इन तमाम बहसों के बीच एक ऐसा प्रश्न है,जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, फिर भी सबसे कम पूछा जाता है। आखिर यही बच्चे,जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश करते हैं,उनमें से कुछ आगे चलकर ऐसे डॉक्टर क्यों बन जाते हैं जिनके व्यवहार को लेकर समाज में असंतोष दिखाई देता है? क्यों कभी-कभी मरीज को लगता है कि उसके सामने बैठा व्यक्ति पहले डॉक्टर नहीं,बल्कि एक व्यवसायी है? यह प्रश्न किसी पूरे चिकित्सक समुदाय पर आरोप नहीं,बल्कि उस व्यवस्था की पड़ताल है जो एक संवेदनशील विद्यार्थी को कभी-कभी संवेदनहीन पेशेवर में बदल देती है।

यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि देश के अधिकांश डॉक्टर आज भी पूरी ईमानदारी,निष्ठा और करुणा के साथ अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि हजारों चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा की। दूर-दराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के बीच कार्य करने वाले डॉक्टर आज भी चिकित्सा सेवा की गरिमा बनाए हुए हैं। इसलिए कुछ लोगों की गलतियों के आधार पर पूरे चिकित्सक समुदाय का मूल्यांकन करना अन्याय होगा। लेकिन यदि समाज में डॉक्टरों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है,तो उसके कारणों पर गंभीरता से विचार करना भी उतना ही आवश्यक है।

समस्या की शुरुआत मेडिकल कॉलेज से भी पहले हो जाती है। आज डॉक्टर बनने की तैयारी एक प्रतियोगी उद्योग बन चुकी है। कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को सफलता का अर्थ केवल रैंक,अंक और सीट समझाया जाता है। चिकित्सा को सेवा नहीं,बल्कि उपलब्धि और प्रतिष्ठा का माध्यम मानने की मानसिकता धीरे-धीरे विकसित होने लगती है। जब लक्ष्य केवल किसी भी कीमत पर मेडिकल सीट प्राप्त करना रह जाए,तब संवेदनशीलता,सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों की चर्चा पीछे छूट जाती है।

इसके बाद यदि कोई छात्र अत्यधिक महँगे निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेता है,जहाँ शिक्षा पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये तक खर्च होते हैं, तो आर्थिक दबाव भी उसके भविष्य को प्रभावित करता है। कई परिवार कर्ज लेकर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह भावना जन्म लेती है कि अब इस निवेश की भरपाई करनी है। यह सोच चिकित्सा की मूल भावना के विपरीत है, लेकिन शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण ने इस मानसिकता को कहीं न कहीं जन्म दिया है।

मेडिकल शिक्षा स्वयं भी अत्यंत कठिन है। वर्षों तक लगातार अध्ययन, इंटर्नशिप की लंबी ड्यूटी,रातभर जागकर काम करना,गंभीर मरीजों से रोज़ सामना होना,मानसिक तनाव और कई बार कठोर प्रशिक्षण–यह सब एक युवा छात्र के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यदि इस दौरान उसे भावनात्मक सहयोग, नैतिक चिकित्सा और मानवीय व्यवहार का पर्याप्त प्रशिक्षण न मिले,तो धीरे-धीरे मरीज एक इंसान नहीं,बल्कि एक केस बनकर रह जाता है।

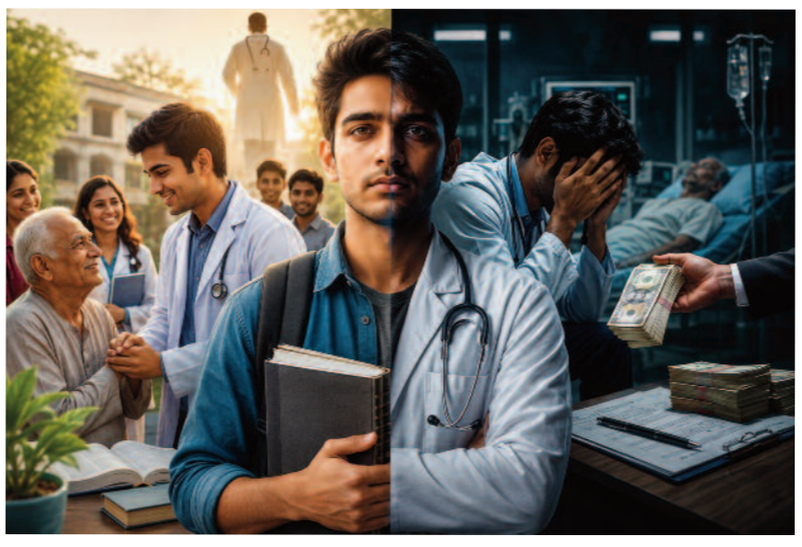

सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। एक-एक डॉक्टर को सैकड़ों मरीज देखने पड़ते हैं। सीमित संसाधनों,दवाओं की कमी और प्रशासनिक दबाव के बीच हर मरीज को पर्याप्त समय देना कई बार संभव नहीं होता। दूसरी ओर निजी अस्पतालों में कई स्थानों पर आय, पैकेज और लक्ष्य आधारित कार्य संस्कृति का दबाव रहता है। ऐसे माहौल में चिकित्सा सेवा और व्यापार के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। समस्या केवल डॉक्टरों की भी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा ढाँचा कई बार ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करता है जहाँ मानवीय संवेदनाएँ धीरे-धीरे थकने लगती हैं। लगातार तनाव, मुकदमों का डर, हिंसा की घटनाएँ, सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के आरोप और हर परिस्थिति में चमत्कार की अपेक्षा–ये सभी बातें डॉक्टरों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव डालती हैं। जब समाज और व्यवस्था दोनों किसी पेशे को लगातार तनाव में रखें, तो उसका असर व्यवहार पर पड़ना स्वाभाविक है।

इसके बावजूद यह स्वीकार करना होगा कि कुछ डॉक्टरों द्वारा अनावश्यक जाँचें लिखना,कमीशन आधारित रेफरल देना, अत्यधिक शुल्क लेना या मरीज के साथ असम्मानजनक व्यवहार करना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। चिकित्सा केवल ज्ञान का नहीं,बल्कि विश्वास का भी पेशा है। एक बार यदि यह विश्वास टूटता है तो उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है।

सबसे बड़ी कमी शायद हमारी चिकित्सा शिक्षा में नैतिक प्रशिक्षण की है। मेडिकल विद्यार्थियों को शरीर की संरचना, रोगों की पहचान और आधुनिक उपचार पद्धतियाँ तो विस्तार से पढ़ाई जाती हैं,लेकिन करुणा, संवाद,सहानुभूति और चिकित्सा नैतिकता को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती,जितनी मिलनी चाहिए। जबकि मरीज को सबसे पहले दवा नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। कई बार डॉक्टर का एक मधुर शब्द भी उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है।

नीट पर होने वाली बहस केवल परीक्षा की निष्पक्षता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यदि हमें वास्तव में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए तो मेडिकल शिक्षा को केवल ज्ञान और तकनीक तक सीमित रखने के बजाय उसे मानवीय मूल्यों से भी जोड़ना होगा। मेडिकल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा,सामुदायिक सेवा,ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर, संवाद कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को यह समझाना होगा कि चिकित्सा केवल जीविका का साधन नहीं,बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी है।

सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, निजी मेडिकल शिक्षा की फीस को अधिक न्यायसंगत बनाने,सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। जब व्यवस्था ही संतुलित होगी, तभी उससे निकलने वाले पेशेवर भी अधिक संतुलित होंगे।

समाज को भी आत्ममंथन करना चाहिए। डॉक्टर से चमत्कार की अपेक्षा करना,छोटी-सी असफलता पर हिंसा करना या बिना तथ्यों के पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। डॉक्टर और मरीज का संबंध विश्वास पर आधारित होता है और इस विश्वास की रक्षा दोनों पक्षों को मिलकर करनी होगी।

नीट की निष्पक्षता आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक यह सुनिश्चित करना है कि मेडिकल कॉलेज से निकलने वाला प्रत्येक डॉक्टर केवल सफल परीक्षार्थी न हो, बल्कि संवेदनशील इंसान भी हो। देश को ऐसे चिकित्सकों की आवश्यकता है जिनके हाथों में विज्ञान की दक्षता हो, मस्तिष्क में ज्ञान हो और हृदय में करुणा। क्योंकि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सबसे पवित्र सेवाओं में से एक है।

नीट के विवादों के बीच यदि हम इस बड़े प्रश्न पर भी गंभीरता से विचार कर सकें कि डॉक्टर बनने की यात्रा में संवेदनाएँ क्यों कमजोर पड़ जाती हैं, तो शायद भविष्य में हमें केवल उत्कृष्ट चिकित्सक ही नहीं,बल्कि ऐसे डॉक्टर भी मिलेंगे जिन पर मरीज बिना किसी भय और संदेह के अपना जीवन सौंप सके। किसी भी राष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था की असली पहचान उसकी मशीनों, भवनों या तकनीक से नहीं, बल्कि डॉक्टर और मरीज के बीच मौजूद विश्वास से होती है। उस विश्वास को बचाए रखना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

CMYK

अपचारी बच्चों की फरारी का सिलसिला जारी...
प्लेस ऑफ सेफ्टी और संप्रेक्षण गृह 2-2 से बराबर

6 महीने में 4 बार सुरक्षा व्यवस्था फेल

2026 फरारी की टाइमलाइन

- **17 फरवरी 2026** – प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 अपचारी बच्चे फरार
- **24 जून 2026** – बाल संप्रेक्षण गृह से 11 अपचारी बच्चे फरार
- **14 जुलाई 2026** – बाल संप्रेक्षण गृह से 13 अपचारी बच्चे फरार
- **23 जुलाई 2026** – प्लेस ऑफ सेफ्टी से 3 अपचारी बच्चे फरार

2012 से खाली
जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद
प्रभारी के भरोसे चल रहा पूरा तंत्र

बैठक दिन में...फरारी रात में ! | सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवाल | आखिर कब जागेगा बाल संरक्षण तंत्र ?

6 महीने में चौथी फरारी : प्लेस ऑफ सेफ्टी और बाल संप्रेक्षण गृह 2-2 से बराबर,आखिर कब जागेगा बाल संरक्षण तंत्र?

बैठक दिन में,रात में फिर फरारी...2012 से खाली जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद,प्रभारी व्यवस्था के भरोसे चल रहा पूरा तंत्र

बैठक दिन में...फरारी रात में...24 घंटे भी नहीं टिक सकी बाल संरक्षण व्यवस्था

15...11...13...अब 3 फिर फरार,अपचारी बच्चों की भागमभाग पर क्यों नहीं लग रही लगाम?

प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाम संप्रेक्षण गृह,फरारी का स्कोर 2-2,हार गई पूरी व्यवस्था

बार-बार फरारी, हर बार जांच...फिर भी नहीं बदली व्यवस्था, छह महीने में चार बार टूटा सुरक्षा घेरा

2012 से जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद खाली, छह महीने में चार फरारी ने खोली पूरे तंत्र की पोल

बाल संरक्षण या 'फरारी केंद्र'? छह महीने में 42 अपचारी बच्चे भागे,जवाबदेही अब भी अधूरी

फरारी की बराबरी: प्लेस ऑफ सेफ्टी और संप्रेक्षण गृह 2-2 से बराबर,सुरक्षा व्यवस्था फिर बेबस

दैनिक घटती-घटना लगातार उठाता रहा सवाल,फिर भी नहीं हुआ अपेक्षित सुधार।

-संवाददाता-
अंबिकापुर,24 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

बाल संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य कानून से संघर्षरत बच्चों को सुरक्षित वातावरण, परामर्श, शिक्षा और सुधार का अवसर देना होता है, लेकिन अंबिकापुर में संचालित प्लेस ऑफ सेफ्टी और बाल संप्रेक्षण गृह अब अपने मूल उद्देश्य से अधिक लगातार होने वाली फरारी की घटनाओं के कारण चर्चा में हैं,वर्ष 2026 के केवल छह महीनों में चार बार अपचारी बच्चों के फरार होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, सबसे चिंताजनक बात यह है कि हर घटना के बाद जांच,समीक्षा,निर्देश और कार्रवाई के दावे किए गए,लेकिन व्यवस्था में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दिया,अब स्थिति यह है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी और बाल संप्रेक्षण गृह दोनों से दो-दो बार बच्चे फरार हो चुके हैं, यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा प्रतीत होता है मानो दोनों संस्थानों के बीच अनचाही 'बराबरी' की स्थिति बन गई हो,यह तुलना व्यंग्यात्मक जरूर है, लेकिन इसके पीछे छिपा सच बेहद गंभीर है–बाल संरक्षण व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है।

बता दे की चार घटनाएं,चार जांचें,कई बैठकें,अनेक निर्देश और लगातार उठते सवाल

फिर भी सुरक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता,यदि सुधार गृहों से ही बच्चे बार-बार फरार हो रहे हैं,तो यह केवल संस्थानों की सुरक्षा का नहीं, बल्कि पूरे बाल संरक्षण तंत्र की कार्यप्रणाली का विषय बन जाता है, अब आवश्यकता केवल जांच की नहीं,बल्कि जवाबदेही तय करने, रिक्त पदों को भरने, सुरक्षा मानकों की स्वतंत्र समीक्षा कराने और ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित करने की है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके,तभी बाल संरक्षण व्यवस्था अपने वास्तविक उद्देश्य के अनुरूप प्रभावी और विश्वसनीय बन पाएगी।

छह महीने...चार बड़ी घटनाएं-सबसे पहली बड़ी घटना 17 फरवरी 2026 को सामने आई, जब महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन संचालित प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 अपचारी किशोर दीवार फांदकर फरार हो गए, इस घटना ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे, इसके बाद 24 जून 2026 को बाल संप्रेक्षण गृह से 11 अपचारी बालक खिड़की तोड़कर फरार हो गए, विभाग ने जांच के आदेश दिए और सुरक्षा मजबूत करने का दावा किया, लेकिन सुधार के दावों की पोल 14 जुलाई 2026 को फिर खुल गई, जब इसी बाल संप्रेक्षण गृह से 13 अपचारी बच्चे दोबारा भाग निकले। लगातार दूसरी घटना ने स्पष्ट कर दिया कि पहले की चूक से कोई ठोस सबक नहीं लिया गया, इसके बाद 23 जुलाई 2026 की रात प्लेस ऑफ सेफ्टी से तीन अपचारी बच्चे खिड़की तोड़कर फरार हो गए, इस घटना के साथ ही दोनों संस्थानों से फरारी की घटनाओं का आंकड़ा दो-दो पर पहुंच गया।

2012 से खाली जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद-पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, जानकारी के अनुसार अंबिकापुर में जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद वर्ष 2012 से रिक्त है, करीब 14 वर्षों से पूरा जिला प्रभारी अधिकारी के भरोसे संचालित हो रहा है, बाल संरक्षण जैसी संवेदनशील व्यवस्था में जहां नियमित निरीक्षण, निगरानी,संस्थागत सुधार और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण होती है,वहां वर्षों तक नियमित अधिकारी की नियुक्ति नहीं होना कई सवाल खड़े करता है।

क्या प्रभारी व्यवस्था पर्याप्त है?-जिला बाल संरक्षण अधिकारी की जिम्मेदारियों में शामिल हैं बाल संरक्षण संस्थाओं की निगरानी,सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना,निरीक्षण करना,बच्चों के पुनर्वास कार्यक्रमों की निगरानी, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय,राज्य और जिला स्तर पर रिपोर्टिंग, ऐसे में यदि वर्षों तक पूरा तंत्र प्रभारी व्यवस्था पर चलता रहे तो यह स्वाभाविक प्रश्न है कि क्या इसका असर संस्थानों की कार्यप्रणाली पर पड़ा है?

हर घटना के बाद वही प्रक्रिया- हर बार घटना होती है, जांच समिति बनती है, रिपोर्ट तैयार होती है,सुरक्षा मजबूत करने की बात होती है,जवाबदेही तय करने की घोषणा होती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर कोई नई फरारी हो जाती है, ऐसे में जनता यह जानना चाहती है कि क्या पिछली जांच रिपोर्टों पर अमल हुआ? क्या सुरक्षा ऑडिट कराया गया? क्या खिड़कियां, दीवारें और सुरक्षा उपकरण सुधारे गए? यदि सुधारे गए तो फिर बच्चे बार-बार कैसे भाग रहे हैं?

अब स्कोर 2-2...लेकिन हार पूरी व्यवस्था की...

यदि घटनाओं को क्रमवार देखा जाए तो पहले प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 बच्चे भागे, फिर बाल संप्रेक्षण गृह से 11 बच्चे भागे, इसके बाद फिर बाल संप्रेक्षण गृह से 13 बच्चे फरार हुए, अब प्लेस ऑफ सेफ्टी से तीन बच्चे भाग गए,यानी प्लेस ऑफ सेफ्टी - 2 बार बाल संप्रेक्षण गृह - 2 बार यह कोई प्रतियोगिता नहीं है,बल्कि यह बताने वाला आंकड़ा है कि दोनों संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था समान रूप से सवालों के घेरे में है।

सबसे बड़ा संयोग या सबसे बड़ी विफलता?

23 जुलाई की घटना इसलिए और अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि उसी दिन कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली थी,बैठक में अपचारी बच्चों के बार-बार फरार होने के मामलों पर चर्चा हुई, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई,यह भी कहा गया कि यदि भविष्य में फिर बच्चे भागे तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी,लेकिन विडंबना देखिए बैठक खत्म हुई और उसी रात प्लेस ऑफ सेफ्टी से तीन बच्चे फरार हो गए, यानी बैठक के बाद सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे भी नहीं टिक सकी, अब सवाल यह है कि क्या बैठकों में लिए गए निर्णय केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं?

दैनिक घटती-घटना ने लगातार निभाई अपनी जिम्मेदारी

इस पूरे मामले में दैनिक घटती-घटना ने लगातार अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारी निभाते हुए हर घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया, 17 फरवरी को 15 बच्चों की फरारी से लेकर 24 जून को 11 बच्चों के भागने, 30 जून को व्यवस्था की खामियों पर विशेष रिपोर्ट, 16 जुलाई को तीसरी फरारी के बाद विस्तृत विश्लेषण और अब 23 जुलाई को फिर हुई फरारी तक अखबार ने लगातार सवाल उठाए कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा, समाचारों में सुरक्षा व्यवस्था, जवाबदेही, रिक्त पदों, निगरानी प्रणाली और प्रशासनिक कमियों को तथ्यों के आधार पर सामने रखा गया, इसके बावजूद फरारी की घटनाओं का सिलसिला नहीं रुका। अब लगातार चार घटनाओं के बाद यह प्रश्न और गंभीर हो गया है कि आखिर जांच रिपोर्टों और समीक्षा बैठकों का वास्तविक परिणाम क्या निकला?

अब शासन के सामने कई बड़े सवाल

- आखिर छह महीने में चार बार बच्चे कैसे फरार हो गए?
- दोनों संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था बार-बार क्यों विफल हो रही है?
- क्या सुरक्षा मानकों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाएगा?
- 2012 से खाली जिला बाल संरक्षण अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति कब होगी?
- क्या हर फरारी की घटना में जिम्मेदारी तय हुई?
- क्या संबंधित अधिकारियों पर वास्तविक कार्रवाई हुई?
- क्या अब भी केवल जांच होगी या व्यवस्था में स्थायी सुधार भी होगा?

जनता पूछ रही है...

- फरारी की घटनाएं कब रुकेंगी?
- क्या अगली घटना का इंतजार किया जा रहा है?
- क्या बाल संरक्षण संस्थान वास्तव में सुरक्षित हैं?
- क्या बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल कागजों तक सीमित है?
- क्या वर्षों से रिक्त पदों को भरने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा?

अपचारी बच्चों के फरार होने की घटनाओं की सारणी (वर्ष 2026)

क्रमांक	घटना की तिथि	संस्था	फरार अपचारी बच्चों की संख्या	प्रमुख तथ्य
1	17 फरवरी 2026	प्लेस ऑफ सेफ्टी, अंबिकापुर	15	वर्ष 2026 की पहली बड़ी फरारी, सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे।
2	24 जून 2026	बाल संप्रेक्षण गृह, अंबिकापुर	11	खिड़की तोड़कर फरार होने की घटना, सुरक्षा व्यवस्था फिर कटघरे में।
3	14 जुलाई 2026	बाल संप्रेक्षण गृह, अंबिकापुर	13	20 दिन के भीतर दूसरी बार संप्रेक्षण गृह से फरारी, सुधार के दावों की पोल खुली।
4	23 जुलाई 2026	प्लेस ऑफ सेफ्टी, अंबिकापुर	3	कलेक्टर की समीक्षा बैठक के कुछ घंटों बाद तीन बच्चे खिड़की तोड़कर फरार।

संस्थावार स्थिति

संस्था	फरारी की घटनाएं	कुल फरार बच्चे
प्लेस ऑफ सेफ्टी	2	18 (15+3)
बाल संप्रेक्षण गृह	2	24 (11+13)
कुल	4 घटनाएं	42 अपचारी बच्चे

संस्थावार स्थिति

बिंदु	स्थिति
वर्ष	2026
कुल फरारी की घटनाएं	4
प्लेस ऑफ सेफ्टी से फरारी	2 बार
बाल संप्रेक्षण गृह से फरारी	2 बार
कुल फरार अपचारी बच्चे	42
जिला बाल संरक्षण अधिकारी का पद	2012 से रिक्त
वर्तमान व्यवस्था	प्रभारी अधिकारी के भरोसे संचालन
नवीनतम घटना	23 जुलाई 2026 – कलेक्टर की समीक्षा बैठक के बाद उसी रात 3 बच्चे फरार

CMYK

'प्रमाण दिखाइए' कहने वाले इरशाद आलम अब खुद एफआईआर में सह-आरोपी

कल तक मीडिया में दे रहे थे सफाई,आज इरशाद आलम खुद बने सह-आरोपी,कोतवाली में नया अपराध दर्ज,पुलिस की विवेचना तेज

राजहंस बस संचालक इरशाद आलम सहित छह लोगों पर कोतवाली में एफआईआर,शाबिर आलम एवं उसके बेटे के साथ दर्ज हुआ नया प्रकरण, पुलिस ने शुरू की विवेचना

मीडिया में देते रहे सफाई,अब खुद भी एफआईआर के घेरे में इरशाद आलम

प्रमाण मांगने वाले इरशाद आलम पर भी एफआईआर,गैंगस्टर प्रकरण ने लिया नया मोड़

24 घंटे पहले दे रहे थे सफाई,24 घंटे बाद खुद बने सह-आरोपी

शाबिर आलम प्रकरण में बढ़ा दायरा, अब राजहंस बस संचालक इरशाद आलम पर भी एफआईआर

मीडिया में चुनौती,अब पुलिस की कार्रवाई—इरशाद आलम भी नए प्रकरण में नामजद

-संवाददाता-
अंबिकापुर,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

झारखंड के चर्चित गैंगवार और उससे जुड़े फरार दोषियों के कथित अंबिकापुर कनेक्शन की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है,वैसे-वैसे नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, इसी क्रम में अब राजहंस बस सेवा के संचालक इरशाद आलम भी पुलिस द्वारा दर्ज एक नए प्रकरण में सह-आरोपी बनाए गए हैं, कोतवाली थाना अंबिकापुर में दर्ज अपराध क्रमांक 0510/2026,दिनांक 23 जुलाई 2026 में इरशाद आलम सहित कुल छह लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर शाबिर आलम एवं उसके बेटे कामरान साबरी के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई है। यह घटनाक्रम इसलिए भी चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि पिछले कई दिनों से इरशाद आलम विभिन्न मीडिया मंचों पर लगातार यह कहते रहे थे कि राजहंस बस संचालक बैदुल खान का फरार गैंगस्टरों से कोई संबंध नहीं है और कुछ लोग व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण उनके परिवार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि यदि किसी के पास ऐसे संबंधों के प्रमाण हैं तो उन्हें सामने लाया जाए, अब, नए प्रकरण में उनका स्वयं सह-आरोपी के रूप में नाम सामने आने के बाद शहर में इस पूरे मामले को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है, हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि एफआईआर दर्ज होना या किसी व्यक्ति का सह-आरोपी बनाया जाना दोष सिद्ध होने के समान नहीं है। आरोपों की जांच पुलिस कर रही है और अंतिम निर्णय न्यायालय करेगा।

पहले से भी दर्ज हैं आपराधिक प्रकरण- पुलिस अभिलेखों के अनुसार शाबिर आलम के विरुद्ध पूर्व में भी अंबिकापुर कोतवाली में प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, बताया जाता है कि वर्ष 2024 में भी उनके विरुद्ध मारपीट,गाली-गलौज और धमकी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज हुआ था, इसके अलावा वर्ष 2025 में उनके बेटे कामरान साबरी सहित अन्य लोगों के विरुद्ध भी भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था,इन मामलों की न्यायिक प्रक्रिया अलग-अलग स्तर पर चल रही है।

24 घंटे पहले मंत्री ने कहा था...अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर होगी कार्रवाई

इस पूरे घटनाक्रम से एक दिन पहले एक वीडियो साक्षात्कार में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा था कि सरगुजा जैसे शांत क्षेत्र में अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने यह भी कहा था कि विवेचना को प्रभावित किए बिना पुलिस को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और जो भी व्यक्ति कानून के दायरे में आएगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी, इसके अगले ही दिन इरशाद आलम सहित अन्य लोगों के विरुद्ध नया अपराध दर्ज होने से इस मामले ने नया मोड़ ले लिया।

क्या है नया मामला?

कोतवाली थाना अंबिकापुर में दर्ज अपराध क्रमांक 0510/2026 के अनुसार पुलिस ने इरशाद आलम, जिसान आलम, दिलशाद आलम,सलमान सहित छह लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर शाबिर आलम एवं उसके बेटे कामरान साबरी के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी देने तथा सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज करने के आरोप में मामला दर्ज किया है,पुलिस अब इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

29 जून से शुरू हुई पूरी कहानी

इस पूरे मामले की शुरुआत 29 जून 2026 के आसपास उस समय हुई जब विभिन्न समाचार माध्यमों में यह जानकारी सामने आई कि झारखंड के चर्चित गैंगवार से जुड़े आजीवन कारावास प्राप्त कुछ फरार दोषी लंबे समय से अंबिकापुर क्षेत्र में रह रहे थे,इसके बाद झारखंड पुलिस की कार्रवाई, स्थानीय पुलिस की जांच और विभिन्न समाचारों के कारण यह मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा,बाद में पुलिस ने कथित रूप से फरार आरोपियों को शरण देने के आरोप में राजहंस बस सेवा से जुड़े बैदुल खान के विरुद्ध भी अलग प्रकरण दर्ज किया। उस मामले की जांच भी अभी जारी है।

मीडिया में लगातार दे रहे थे सफाई

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इरशाद आलम लगातार विभिन्न मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते रहे, उनका कहना था कि बैदुल खान का फरार गैंगस्टरों से कोई संबंध नहीं है और उन्हें जानबूझकर विवाद में घसीटा जा रहा है, उन्होंने कई बार यह भी कहा कि राजहंस बस सेवा की सफलता से प्रतिस्पर्धी परेशान हैं और इसी कारण इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, अब नए प्रकरण में उनका नाम आने के बाद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों के बीच चर्चा और तेज हो गई है।

पुलिस की जांच किस दिशा में?

पुलिस फिलहाल दोनों मामलों की अलग-अलग विवेचना कर रही है, जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि विभिन्न आरोपियों की भूमिका क्या रही और उपलब्ध साक्ष्य क्या संकेत देते हैं, अभी तक पुलिस की ओर से विस्तृत प्रेस नोट जारी नहीं किया गया है जिसमें विवेचना के सभी तथ्यों का खुलासा किया गया हो, इसलिए कई बिंदुओं पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।

शहर में चर्चा,लेकिन अंतिम फैसला न्यायालय का...

इस पूरे मामले को लेकर शहर में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं,सोशल मीडिया पर भी अनेक तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं, हालांकि कानूनी दृष्टि से यह याद रखना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होना या उसे सह-आरोपी बनाया जाना, उसे दोषी सिद्ध नहीं करता,आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच, अभियोजन की प्रक्रिया और अंततः न्यायालय के निर्णय के बाद ही होगी।

जांच पर टिकी निगाहें...

अब इस मामले में सभी की निगाहें पुलिस विवेचना पर टिकी हैं,यदि जांच में आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी,वहीं यदि आरोप सिद्ध नहीं होते, तो संबंधित व्यक्तियों को न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप राहत मिलेगी,फिलहाल यह मामला सरगुजा संभाग के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो चुका है,झारखंड से जुड़े फरार दोषियों की जांच,कथित स्थानीय नेटवर्क,दर्ज एफआईआर और लगातार सामने आ रहे नए घटनाक्रमों ने इसे व्यापक सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया है, आने वाले दिनों में पुलिस विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया से ही यह स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितना तथ्य है और किसकी क्या भूमिका रही, तब तक इस मामले में किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा।

दोस्तों संग शराब पार्टी कर रहे युवक का अपहरण,बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या

जमीन विवाद में वारदात की आशंका,बेहोशी की हालत में सड़क किनारे मिला था घायल,इलाज के दौरान मौत

-संवाददाता-
प्रतापपुर/सूरजपुर,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम गोंदा में जमीन विवाद ने एक युवक की जान ले ली। दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहे युवक का कथित तौर पर अपहरण कर 10-15 युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में सड़क किनारे मिले युवक की मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ग्राम गोंदा निवासी हरिनंदन राजवाड़े (36) के घर 23 जुलाई की दोपहर अंबिकापुर से उसके दो दोस्त तुषार और राहुल पहुंचे थे। तीनों गांव के ही राजेंद्र प्रसाद के घर गए,जहां चारों शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ललित को इसकी जानकारी मिली। आरोप है कि वह 10-15 युवकों के साथ वहां पहुंचा,गाली-गलौज करते हुए हरिनंदन को जबरन चारपहिया वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गया। घटना की जानकारी मिलने पर हरिनंदन के बड़े भाई बमभोला राजवाड़े परिजनों और ग्रामीणों के साथ उसकी तलाश में निकले। काफी खोजबीन के बाद हरिनंदन भैंसामुंडा से लगे ग्राम केवरा चौक के पास सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल और बेहोशी की हालत में मिला। उसके शरीर पर डंडे सहित अन्य हथियारों से मारपीट के कई निशान थे और खून बह रहा था। परिजन तत्काल उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान देर रात करीब 2 बजे उसकी मौत हो गई। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

15 दिन पहले भी हुआ था विवाद

परिजनों के अनुसार हरिनंदन और गांव के ललित के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। करीब 15 दिन पहले भी दोनों पक्षों में इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस जमीन विवाद को हत्या की वजह मानते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है।

जिला न्यायालय परिसर में स्टैंड और फोटो कॉपी दुकान आवंटन पर उठे सवाल

बोलीदाताओं ने पारदर्शिता पर खड़े किए प्रश्न, नियमों की अनदेखी कर दूसरे को आवंटन का आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

जिला न्यायालय परिसर में वाहन स्टैंड और फोटोकॉपी दुकान के आवंटन को लेकर विवाद गहरा गया है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ आवेदकों ने आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नियमों के अनुरूप पात्र होने के बावजूद उन्हें दुकान का आवंटन नहीं किया गया, जबकि किसी अन्य व्यक्ति के नाम आवंटन कर दिया गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि निविदा प्रक्रिया के दौरान उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि नियमानुसार कार्रवाई होगी, लेकिन अंतिम परिणाम में नियमों की अनदेखी की गई। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और आवंटन को लेकर स्पष्ट जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा अंबिकापुर की ओर से जिला न्यायालय परिसर में वाहन स्टैंड एवं फोटोकॉपी दुकान के संचालन के लिए 13 से 23 जुलाई तक निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। 24 जुलाई को निविदा खोलने की प्रक्रिया निर्धारित थी। इसके बाद आवंटन को लेकर विवाद सामने आ गया। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि मामले में जानकारी लेने और सवाल पूछने पर समिति के सदस्य स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं। इससे पूरी प्रक्रिया को लेकर संदेह और बढ़ गया है। प्रभावित पक्ष ने निष्पक्ष जांच कर नियमों के अनुरूप पात्र आवेदकों को न्याय दिलाने की मांग की है।

ऑपरेशन क्लीन जारी : इंजेक्शन से महुआ शराब तक लगातार कार्रवाई,लेकिन क्या नशे के असली सरगना अब भी पकड़ से दूर?

24 घंटे में सप्लायर तक पहुंची टीम,अब गंगापुर में 200 किलो महुआ लाहन और 15 लीटर शराब जब्त...लगातार सफल दबिशों के बीच बड़ी सप्लाई चेन पर उठ रहे सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

संभागीय आबकारी उड़नदस्ता द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत नशीले इंजेक्शन, अवैध शराब और महुआ लाहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। एक ओर टीम पूछताछ के आधार पर आरोपियों से आगे कथित सप्लायर तक पहुंच रही है, वहीं दूसरी ओर हर कार्रवाई के बाद नए नाम सामने आने से यह सवाल भी गहराता जा रहा है कि आखिर इस पूरे अवैध कारोबार की सबसे बड़ी कड़ी कौन है और उस तक कार्रवाई कब पहुंचेगी। हाल ही में ब्रह्मपारा से 28 नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार आशा पांडेय के मामले में आबकारी टीम ने महज 24 घंटे के भीतर उसके बताए कथित सप्लायर राजेश मंदिलवार उर्फ बुटन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। विभाग के अनुसार पूछताछ में आशा पांडेय ने बताया था कि वह इंजेक्शन बुटन से खरीदती थी। इसी आधार पर उसे हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता का कहना है कि ब्रह्मपारा पहले ब्राउन शुगर के कारोबार के लिए बदनाम रहा है और अब वहां कुछ लोग नशीले इंजेक्शनों के अवैध कारोबार में सक्रिय हैं। विभाग का दावा है कि आशा पांडेय फुटकर स्तर पर बिक्री करती थी, जबकि बुटन कथित रूप से थोक सप्लायर की भूमिका में था। इसी बीच शुक्रवार को उड़नदस्ता ने गंगापुर के नालापारा में मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर विजय गिरी के घर से 15 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब,200 किलोग्राम महुआ लाहन तथा चलती हुई भट्ठी बरामद की। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक रमेश दुबे,प्रधान आरक्षक अशोक सोनी,नगर सैनिक रोहित सोनवानी एवं महिला सैनिक राजकुमारी सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

हर कार्रवाई के बाद अगली कड़ी तक पहुंच रही टीम : पिछले कुछ सप्ताह में आबकारी उड़नदस्ता ने लगभग हर मामले में पूछताछ के आधार पर आगे की कड़ी तक पहुंचने का दावा किया है। वाहिद अंसारी से मोशीम अंसारी,श्याम लॉज से साहिल तिर्की और फिर नितीश गुप्ता, सीतापुर में सजाद अली से महबूब खान तथा अब आशा पांडेय से राजेश मंदिलवार उर्फ बुटन तक कार्रवाई पहुंची। इससे स्पष्ट है कि टीम केवल बरामदगी तक सीमित नहीं रहकर सप्लाई चेन की अगली कड़ियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

कार्रवाइयां बढ़ीं,लेकिन कारोबार क्यों नहीं थम रहा?

लगातार दबिशों में नशीले इंजेक्शन, हजारों प्रतिबंधित कैप्सूल,महुआ शराब और लाहन बरामद हो रहे हैं। इससे विभाग की सक्रियता तो दिखाई देती है,लेकिन साथ ही यह भी सामने आता है कि नशे का अवैध कारोबार अभी भी अलग-अलग स्वरूपों में जारी है। यदि लगातार कार्रवाई के बाद भी नए आरोपी और नए सप्लायर सामने आ रहे हैं, तो यह संकेत है कि नेटवर्क की जड़ें अभी पूरी तरह नहीं कट सकी हैं।

सबसे बड़ा सवालः आखिर ऊपर कौन है?

लगातार सफल कार्रवाई के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। स्थानीय स्तर के विक्रेता और कथित सप्लायर गिरफ्तार हो रहे हैं,लेकिन इनके ऊपर मौजूद उस बड़ी आपूर्ति श्रृंखला का अब तक खुलासा नहीं हो सका है,जहां से नशीले इंजेक्शन, कैप्सूल और अन्य मादक पदार्थ जिले में पहुंच रहे हैं। आम लोगों की अपेक्षा अब केवल छोटी-छोटी गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है,बल्कि वे चाहते हैं कि जांच उस मास्टर नेटवर्क तक पहुंचे,जिससे इस अवैध कारोबार पर स्थायी रोक लग सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि जांच केवल फुटकर विक्रेताओं और स्थानीय सप्लायरों तक ही सीमित रही तो कुछ दिनों बाद फिर नए नाम सामने आएंगे। नशे के कारोबार पर वास्तविक अंकुश तभी संभव होगा, जब उसकी पूरी सप्लाई चेन और उसे संचालित करने वाले मुख्य सरगनाओं तक कानून का हाथ पहुंचे।

दिनदहाड़े शिक्षिका के सूने मकान में चोरी,सीसीटीवी से पकड़ाए नाबालिग

जेवर,नकदी और कांसा-पीतल के बर्तन पार...कबाड़ी को बेचने का आरोप,दो नाबालिग व कबाड़ी हिरासत में

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर में नाबालिगों द्वारा चोरी की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। ताजा मामला केदारपुर पानी टंकी के पास का है, जहां एक निजी स्कूल की शिक्षिका के सूने मकान का पीछे का दरवाजा तोड़कर तीन नाबालिगों ने दिनदहाड़े चोरी कर ली। आरोप है कि चोरी का सामान बाद में एक कबाड़ी को बेच दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो नाबालिग और एक कबाड़ी को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार केदारपुर निवासी सरिता सिन्हा निजी स्कूल में शिक्षिका हैं। 22 जुलाई की सुबह करीब 7.30 बजे वह घर में ताला लगाकर स्कूल गई थीं। दोपहर करीब 3 बजे लौटने पर घर का सामान बिखरा मिला और पीछे का दरवाजा टूटा हुआ था। जांच करने पर सोने की एक चेन, चार अंगूठियां, चांदी के सिक्के, कांसा-पीतल के बर्तन, नकदी सहित अन्य कीमती सामान गायब मिला।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात : घटना की जानकारी मिलने पर पड़ोसियों के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। फुटेज में दोपहर 12.54 बजे तीन नाबालिग मकान की ओर जाते दिखाई दिए, जबकि 2.35 बजे वे एक बोरी में सामान लेकर बाहर निकलते हुए कैद हुए।

कबाड़ी से पूछताछ जारी : शिक्षिका के पति की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो नाबालिगों और एक कबाड़ी को हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में चोरी का सामान कबाड़ी को बेचे जाने की बात सामने आई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर चोरी का सामान बरामद करने का प्रयास कर रही है।

राजस्व न्यायालय का बड़ा फैसला : सरकारी सड़क की जमीन से रितेश अग्रवाल को बेदखल करने का आदेश

सूरजपुर में सरकारी सड़क पर कब्जे मामले में ट्रिपल स्टोरी भवन पर चला राजस्व विभाग का डंडा...

- शासकीय सड़क पर अतिक्रमण साबित,ट्रिपल स्टोरी भवन हटाने का आदेश...
- सरकारी भूमि पर ट्रिपल स्टोरी भवन! तीन दिन में अतिक्रमण हटाओ,वरना होगी बेदखली...
- अतिक्रमण पर राजस्व का बड़ा एक्शन : सरकारी सड़क पर बने भवन को हटाने का आदेश...
- सड़क पर भवन खड़ा हो गया और सिस्टम देखता रहा! अब तहसीलदार ने जारी किया बेदखली आदेश
- खसरा क्रमांक 2630 की शासकीय सड़क भूमि पर 0.033 हेक्टेयर में ट्रिपल स्टोरी भवन,कार्यालय,फैक्ट्री और बाउंड्रीवाल निर्माण को माना अतिक्रमण...तीन दिन में पालन नहीं होने पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई।

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। सूरजपुर शहर में शासकीय सड़क की भूमि पर कथित अतिक्रमण कर ट्रिपल स्टोरी भवन, कार्यालय,फैक्ट्री और बाउंड्रीवाल निर्माण किए जाने के मामले में तहसीलदार न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है,लंबी सुनवाई, राजस्व अभिलेखों,पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट,दोनों पक्षों के तर्क तथा उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भों पर विचार करने के बाद तहसीलदार ने भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित अनावेदक रितेश अग्रवाल (पिता-सुरेश अग्रवाल) को शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया है,न्यायालय ने तीन दिवस के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं होता है,तो राजस्व विभाग नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई करेगा।

क्या है पूरा मामला?

राजस्व अभिलेखों के अनुसार सूरजपुर नगर स्थित खसरा क्रमांक 2630,कुल रकबा 1.975 हेक्टेयर शासकीय सड़क मद में दर्ज है,पटवारी हल्का क्रमांक-08 द्वारा न्यायालय को प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि उक्त शासकीय भूमि में से लगभग 0.033 हेक्टेयर क्षेत्र पर रितेश अग्रवाल द्वारा ट्रिपल स्टोरी भवन,कार्यालय,फैक्ट्री तथा बाउंड्रीवाल का निर्माण कर कब्जा किया गया है,रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर विधिवत सुनवाई प्रारंभ की गई, राजस्व विभाग का कहना था कि सड़क मद में दर्ज भूमि पर निजी निर्माण किया जाना कानूनन अतिक्रमण की श्रेणी में आता है,इसलिए कार्रवाई आवश्यक है।

आपत्तिकर्ता ने उठाया सरकारी भूमि पर कब्जे का मुद्दा-प्रकरण में आपत्तिकर्ता कुंजबिहारी गुप्ता ने न्यायालय में विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा कि शासकीय सड़क की भूमि पर पक्का भवन बनाकर फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है,उन्होंने तर्क दिया कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निजी कब्जा न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों का भी हनन है,उन्होंने न्यायालय से तत्काल अतिक्रमण हटाने की मांग की, सुनवाई के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर के रिट क्रमांक 866/2026 (डी.के. सोनी एवं अन्य बनाम शासन) में पारित आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की और कहा कि मामले का शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने क्यों नहीं माना बचाव पक्ष का तर्क?-सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट,राजस्व अभिलेख,दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा आपत्तियों का परीक्षण किया,न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संबंधित भूमि शासकीय सड़क मद में दर्ज है और उस पर निर्माण कर कब्जा किया जाना प्रमाणित होता है,न्यायालय ने यह भी माना कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अतिक्रमण के निष्कर्ष को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसी आधार पर भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 248 के तहत अतिक्रमण हटाने एवं बेदखली का आदेश पारित किया गया।

तीन दिन का समय, फिर होगी प्रशासनिक कार्रवाई-तहसीलदार न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि संबंधित अनावेदक तीन दिवस के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाकर न्यायालय में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, यदि निर्धारित अवधि में ऐसा नहीं किया जाता है तो राजस्व विभाग स्वयं नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई करेगा, इस आदेश के बाद अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसे समयबद्ध तरीके से लागू कराने की होगी।

अनावेदक ने पटवारी रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल

दूसरी ओर अनावेदक रितेश अग्रवाल ने न्यायालय के समक्ष विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर पूरे प्रकरण को चुनौती दी,उन्होंने कहा कि पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार पंचनामा पक्षपातपूर्ण है और उनकी अनुपस्थिति में तैयार किया गया,उनके अनुसार पंचनामा बनाते समय उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई और न ही उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई,उन्होंने यह भी कहा कि पुराने राजस्व नक्शों का सही परीक्षण नहीं किया गया तथा जिस कथित सड़क का उल्लेख किया जा रहा है,उसकी वास्तविक चौड़ाई और सीमाएं वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित नहीं की गई,उनका दावा था कि जिस भूमि पर निर्माण है, वहां उनका परिवार तीन पीढ़ियों से व्यापार कर रहा है और किसी प्रकार का नया अतिक्रमण नहीं किया गया,उन्होंने न्यायालय से दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुन: सीमांकन कराने,संयुक्त स्थल निरीक्षण कराने तथा आधुनिक सर्वे तकनीक के माध्यम से वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

सूरजपुर शहर में सरकारी सड़क पर कब्जा,
बना ट्रिपल स्टोरी भवन! तहसीलदार न्यायालय ने जारी किय बेख्रली आदेश

रितेश अग्रवाल द्वारा रोड की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश

खसरा क्रमांक 2630, कुल रकबा 1.975 हेक्टयर शासकीय सड़क मद में दर्ज

लगभग 0.033 हेक्टयर पर ट्रिपल स्टोरी भवन, कार्यालय, फैक्टरी एवं बॉउंडीवाल का निर्माण

तीन दिवस में अतिक्रमण हटाने के निर्देंस, नहीं हटाने पर होगी बेदखली की कार्रवाई

अब उठ रहे हैं कई अहम सवाल....

यह मामला केवल एक अतिक्रमण तक सीमित नहीं रह गया है,बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कई गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है, सबसे पहला सवाल यह है कि यदि निर्माण वास्तव में शासकीय सड़क की भूमि पर हुआ,तो ट्रिपल स्टोरी भवन,कार्यालय और फैक्ट्री का निर्माण पूरा होने तक संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या निर्माण के दौरान नगर पालिका,राजस्व विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों ने कोई निरीक्षण किया था? तीसरा सवाल यह है कि यदि अनावेदक की ओर से लगाए गए आरोप सही हैं और सीमांकन या पंचनामा प्रक्रिया में कोई त्रुटि हुई है, तो क्या इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी?

क्या आगे बढ़ेगा कानूनी विवाद?

राजस्व न्यायालय का आदेश आने के बाद संभावना है कि संबंधित पक्ष उच्च न्यायालय या सक्षम न्यायिक मंच का दरवाजा खटखटा सकता है, यदि ऐसा होता है तो पूरे प्रकरण की कानूनी समीक्षा उच्च स्तर पर भी हो सकती है, वहीं यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो राजस्व विभाग को पुलिस बल के सहयोग से बेदखली की कार्रवाई करनी पड़ सकती है।

अब प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें...

सूरजपुर शहर के चर्चित इस प्रकरण में तहसीलदार न्यायालय ने अपना निर्णय सुना दिया है,अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आदेश के क्रियान्वयन का है, यदि तीन दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है,तो यह देखना होगा कि प्रशासन कितनी तत्परता और निष्पक्षता से कार्रवाई करता है,हालांकि,यह भी उल्लेखनीय है कि अनावेदक ने न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षण और सीमांकन प्रक्रिया पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं, यदि वे आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हैं,तो मामले की आगे की दिशा न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी,फिलहाल तहसीलदार न्यायालय का आदेश प्रभावी है और प्रशासन के सामने उसे लागू कराने की जिम्मेदारी है।

जनपद पंचायत खड़गवां की निगरानी पर सवाल : ग्राम पंचायत सिंघत में विकास हुआ या योजनाओं की राशि में खेल?

बारेलाल ट्रेडर्स के नाम से लगातार भुगतान,पात्रता पर उठे सवाल,शिकायत की जांच भी बनी विवाद का विषय

राजेन्द्र शर्मा

खड़गवां,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले की जनपद पंचायत खड़गवां अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंघत एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में है,ग्रामीणों ने पंचायत में वर्ष 2021 से अब तक हुए विकास कार्यों,शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय भुगतान और हितग्राही चयन में व्यापक अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं,उनका कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तो पंचायत स्तर से लेकर जनपद पंचायत स्तर तक कई गंभीर तथ्य सामने आ सकते हैं,हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और संबंधित मामले की आधिकारिक जांच शेष है।

'बारेलाल ट्रेडर्स' के नाम से लगातार भुगतान पर सवाल....

ग्रामीणों का आरोप है कि वर्ष 2021 से वर्तमान तक ग्राम पंचायत सिंघत में 'बारेलाल ट्रेडर्स' के नाम से लगातार बिल लगाकर पंचायत निधि से भुगतान किया गया,उनका दावा है कि जिन कार्यों के नाम पर राशि निकाली गई,उनमें से कई कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देते या अधूरे हैं,ग्रामीणों का कहना है कि यदि पंचायत के बिल-वाउचर, माप पुस्तिका (एमबी), कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और भुगतान अभिलेखों की जांच कराई जाए तो वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में भी पात्रता पर सवाल...

ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही चयन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, उनका आरोप है कि पंचायत में ऐसे लोगों को आवास का लाभ दिया गया जिनके पास पहले से पर्याप्त भूमि,ट्रैक्टर, बोलेरो और अन्य संसाधन उपलब्ध हैं, वहीं कई गरीब और वास्तविक पात्र परिवार आज भी योजना के लाभ से वंचित हैं,आरोप यह भी है कि कुछ स्वीकृत आवासों का निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ,लेकिन पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया, यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह हितग्राही चयन और भुगतान प्रक्रिया दोनों पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है।

स्वच्छता और अन्य योजनाओं में भी अनियमितता के आरोप...

ग्रामीणों का कहना है कि केवल आवास योजना ही नहीं बल्कि शौचालय,स्वच्छता और अन्य पंचायत योजनाओं में भी पात्रता नियमों का पालन नहीं किया गया, उन्होंने मांग की है कि पंचायत की सभी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) और वित्तीय ऑडिट कराया जाए।

सबसे बड़ा सवाल जनपद पंचायत खड़गवां की भूमिका पर...

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्न जनपद पंचायत खड़गवां की निगरानी व्यवस्था पर उठ रहा है,ग्रामीण पूछ रहे हैं कि जब पंचायत से प्रत्येक प्रस्ताव,प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति और भुगतान संबंधी दस्तावेज जनपद कार्यालय भेजे जाते हैं,तो संबंधित अधिकारी बिना पर्याप्त सत्यापन के स्वीकृति कैसे प्रदान कर देते हैं? यदि पंचायत स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं, तो क्या केवल सरपंच और सचिव जिम्मेदार होंगे या फिर उन प्रस्तावों को स्वीकृति देने वाले अधिकारी भी जवाबदेह होंगे?

शिकायत की जांच भी सवालों के घेरे में...

ग्रामीणों ने शिकायत की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं,उनका कहना है कि शिकायत मिलने के बाद जनपद पंचायत खड़गवां से दो अधिकारी जांच के लिए ग्राम पंचायत सिंघत पहुंचे, लेकिन उन्होंने शिकायतकर्ता को पूर्व सूचना नहीं दी,ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर केवल औपचारिकता पूरी की और वापस लौट गए,उनका यह भी आरोप है कि शिकायतकर्ता को जांच की तिथि पहले से बताने के बजाय जांच अधिकारियों ने केवल पंचायत प्रतिनिधियों को सतर्क करने का काम किया, यदि यह आरोप सही हैं तो जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं।

जनपद पंचायत खड़गवां की निगरानी पर बड़े सवाल!
ग्राम पंचायत सिंघत में योजनाओं की राशि पर डाका?

सरपंच-सचिव की मनमानी या अधिकारियों की मिलीभगत? ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच की मांग

ग्रामीणों के सवाल...

ग्रामीणों ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं वर्ष 2021 से अब तक 'बारेलाल ट्रेडर्स' के नाम हुए भुगतानों की जांच कब होगी? प्रधानमंत्री आवास योजना में कथित अपात्र हितग्राहियों को लाभ देने की जांच कौन करेगा? जनपद पंचायत ने प्रस्तावों और भुगतानों को किस आधार पर स्वीकृति दी? यदि वित्तीय अनियमितता हुई है तो क्या केवल सरपंच और सचिव जिम्मेदार होंगे या संबंधित अधिकारी भी जवाबदेह होंगे? शिकायत की जांच बिना शिकायतकर्ता की उपस्थिति के क्यों की गई?

ग्रामीणों की मांग-हो उच्चस्तरीय जांच

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा संबंधित जांच एजेंसियों से मांग की है कि ग्राम पंचायत सिंघत में वर्ष 2021 से अब तक हुए सभी विकास कार्यों, पंचायत निधि के भुगतान,मस्टर रोल,बिल-वाउचर,प्रधानमंत्री आवास योजना,शौचालय,स्वच्छता योजना तथा अन्य योजनाओं की उच्चस्तरीय,स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, उनका कहना है कि यदि पूरी पारदर्शिता से जांच हुई तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हो सकेगी।

सचिव ने आरोपों से किया इनकार

जब इस संबंध में ग्राम पंचायत सिंघत के सचिव अनुराग दुबे से पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि 'मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। ग्राम सभा में सभी जानकारी दी गई है। '

जांच के बाद ही स्पष्ट होगी सच्चाई

यह मामला फिलहाल ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों और पंचायत सचिव के खंडन पर आधारित है,आरोपों की सत्यता किसी सक्षम एवं निष्पक्ष जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी,यदि जांच में वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितताएं सामने आती हैं तो कार्रवाई पंचायत प्रतिनिधियों तक सीमित रहेगी या जनपद स्तर के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी,यह जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा, फिलहाल ग्रामीणों की निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

करोड़ों की स्ट्रीट लाइट योजना पर सवाल,नई लाइटें भी बंद,गुणवत्ता जांच की मांग तेज

भाजपा नेता एवं चैंबर जिलाध्यक्ष शारदा गुप्ता ने सीएमओ और नपा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन,अमानक सामग्री और घटिया गुणवत्ता के लगाए आरोप

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। बैकुंठपुर नगर पालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से स्थापित की जा रही स्ट्रीट लाइट एवं ट्यूबलर पोल योजना की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं,भाजपा नेता एवं चैंबर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष शारदा गुप्ता ने नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) से मुलाकात कर तथा नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे कार्य की तकनीकी जांच कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शहर में हाल ही में लगाई गई कई नई स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी हैं,जबकि जिन स्थानों पर कार्य अभी जारी है वहां भी अमानक सामग्री और निम्न गुणवत्ता के तारों का उपयोग किए जाने की शिकायत मिल रही है, उनका कहना है कि यदि सतह पर दिखने वाले कार्यों में ही गुणवत्ता का अभाव है, तो ट्यूबलर पोल और अन्य निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर भी प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

करोड़ों की योजना,लेकिन रोशनी अधूरी-शारदा गुप्ता ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बैकुंठपुर नगर पालिका क्षेत्र में बेहतर प्रकाश व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपये की लागत से ट्यूबलर पोल और स्ट्रीट लाइट लगाने की स्वीकृति दी है,उनका कहना है कि सरकार की मंशा शहर को बेहतर और सुरक्षित प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराना है,लेकिन जमीनी स्तर पर कई स्थानों पर नई लाइटें ही बंद पड़ी हैं, इससे योजना के क्रियान्वयन और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अमानक सामग्री के उपयोग का आरोप-ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि स्ट्रीट लाइट कार्यों में मानक गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है,विशेष रूप से बिजली के तार और अन्य उपकरणों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं,शारदा गुप्ता ने मांग की है कि पूरे कार्य का स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण कराया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उपयोग की गई सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं।

बरसात में बढ़ सकती हैं दुर्घटनाएं-उन्होंने कहा कि वर्तमान में वर्षा ऋतु चल रही है और ऐसे समय में सड़कों पर पर्याप्त रोशनी होना अत्यंत आवश्यक है,यदि स्ट्रीट लाइटें बंद रहेंगी तो वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा तथा दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ सकती है।

उच्च अधिकारियों से भी की शिकायत-शारदा गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में संचालक,नगरीय प्रशासन,अंबिकापुर (सरगुजा संभाग) को भी ज्ञापन भेजकर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है,उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई,तो मुख्यमंत्री, संबंधित विभागीय मंत्री तथा अन्य उच्च अधिकारियों के समक्ष भी शिकायत प्रस्तुत की जाएगी।

नगर पालिका ने दिया जांच का आश्वासन-ज्ञापन प्राप्त होने के बाद नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर के अधिकारियों ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, अब देखना यह होगा कि जांच कितनी जल्दी होती है और यदि गुणवत्ता में कमी या अमानक सामग्री के उपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है।

प्रतापपुर के मदननगर में हिंसक झड़प

भूमि अधिग्रहण के दौरान बवाल, डीएसपी समेत 24 से अधिक पुलिसकर्मी घायल

प्रतापपुर के मदननगर में बवाल : भूमि अधिग्रहण और गिरफ्तारी की कार्रवाई के बीच हिंसक झड़प,डीएसपी समेत 24 से अधिक पुलिसकर्मी घायल...

ग्रामीणों के घायल होने की भी सूचना...कई वाहन क्षतिग्रस्त...पुलिस और ग्रामीणों के दावे अलग-अलग...जांच के बाद ही साफ होगी पूरी तस्वीर...

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर/प्रतापपुर,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मदननगर गांव में शुक्रवार को प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान हालात अचानक हिंसक हो गए,घटना में एक डीएसपी सहित 24 से अधिक पुलिस अधिकारी एवं जवान घायल हो गए,जबकि कई ग्रामीणों के घायल होने की भी सूचना है,कई सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा है तथा कुछ वाहनों में आग लगाने के प्रयास की भी जानकारी सामने आई है,घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अंबिकापुर-प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा,हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के अलग-अलग दावे सामने आए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार टीम भूमि अधिग्रहण एवं सर्वे की कार्रवाई के लिए गांव पहुंची थी,जबकि पुलिस की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टीम पूर्व में दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई थी। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे और उसी को लेकर विवाद बढ़ा। ऐसे में घटना की वास्तविक परिस्थितियां जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी।

सुबह शुरू हुई कार्रवाई,कुछ ही देर में बिगड़ गए हालात-जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह प्रशासनिक एवं पुलिस अमला बड़ी संख्या में मदननगर गांव पहुंचा,सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगभग 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, आसपास के जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया था, मौके पर कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर उनकी आपत्तियों और मांगों पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया,प्रशासनिक टीम के पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हो गए,देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और विवाद हिंसक झड़प में बदल गया।

पथराव,धक्का-मुक्की और लाठीचार्ज जैसे हालात...

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, फिर धक्का-मुक्की शुरू हो गई, इसके बाद पथराव और मारपीट की स्थिति बन गई, हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, इसी दौरान पथराव में एक डीएसपी सहित दो दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी एवं जवान घायल हो गए,घटना में कई ग्रामीणों के घायल होने की भी सूचना है, सभी घायलों का उपचार प्रतापपुर एवं धर्मपुर स्वास्थ्य केंद्रों में कराया गया।

सरकारी वाहनों को नुकसान,आग लगाने की कोशिश की भी चर्चा...

घटना के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा कई पुलिस एवं सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने की जानकारी सामने आई है, कुछ वाहनों में आग लगाने का प्रयास किए जाने की भी चर्चा है, हालांकि आगजनी से हुए नुकसान का आधिकारिक विवरण अभी जारी नहीं किया गया है, सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर चक्काजाम-घटना के बाद ग्रामीणों ने अंबिकापुर-प्रतापपुर मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक आवागमन प्रभावित रहा,सुरक्षा कारणों से पुलिस ने मार्ग पर आवाजाही सीमित कर दी और अतिरिक्त बल तैनात किया गया, पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण की स्थिति बताई जा रही है।

पुलिस का पक्षः आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई थी टीम-सूरजपुर पुलिस की ओर से जारी प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस टीम गांव में पूर्व से दर्ज एक गंभीर आपराधिक प्रकरण के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई थी,इसी दौरान ग्रामीणों के विरोध के कारण स्थिति बिगड़ गई और हिंसक झड़प हुई,पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है तथा हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीणों का पक्षः भूमि अधिग्रहण बना विवाद की वजह-दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं,उनका आरोप है कि उनकी आपत्तियों और मांगों पर प्रशासन ने समुचित सुनवाई नहीं की,इसी कारण प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया गया और विवाद बढ़ गया।

दो दावे,एक घटना—जांच के बाद सामने आएगी पूरी सच्चाई-इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना के कारणों को लेकर दो अलग-अलग दावे सामने आए हैं,प्रशासनिक पक्ष के अनुसार कार्रवाई भूमि अधिग्रहण एवं सर्वे से जुड़ी थी, पुलिस का कहना है कि टीम आपराधिक मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई थी,ग्रामीणों का कहना है कि पूरा विवाद भूमि अधिग्रहण के विरोध से जुड़ा है, ऐसे में घटना का वास्तविक कारण और पूरी परिस्थितियां आधिकारिक जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी।

मदननगर मामले की जांच करेगी कांग्रेस की 8 सदस्यीय समिति-मदननगर में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प तथा कथित लाठीचार्ज के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए आठ सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, समिति के संयोजक पूर्व मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह बनाए गए हैं,इसके अलावा पूर्व अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, विधायक जनक ध्रुव, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवती राजवाड़े, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशी सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष जगत आयाम,ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जायसवाल तथा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र दुबे को सदस्य बनाया गया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू द्वारा जारी आदेश के अनुसार समिति मदननगर और प्रभावित गांवों का दौरा कर पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात करेगी,घटनास्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेगी और पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी, समिति के गठन के बाद अब उसकी जांच और रिपोर्ट पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक दोनों स्तरों पर निगाहें टिकी हुई हैं।

घायल पुलिसकर्मियों में शामिल प्रमुख नाम

प्राथमिक जानकारी के अनुसार घायल पुलिसकर्मियों में शामिल हैं अमर सिंह (45 वर्ष), सुखीचंद एक्का (59 वर्ष), नंदकिशोर राजवाड़े (43 वर्ष),फूलमती राजवाड़े, सविता साहू इसके अलावा दो दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी, जवान एवं अन्य लोगों के घायल होने की सूचना है, घायलों का उपचार बीएमओ के निर्देशन में डॉ. विकास गुप्ता, डॉ. आफताब खान तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया गया।

प्रशासन की अगली कार्रवाई...

घटना के बाद पूरे मदननगर गांव एवं आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

एक नजर में...

बिंदु	जानकारी
स्थान	मदननगर, प्रतापपुर (सूरजपुर)
घटना	प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प
घायल	डीएसपी सहित 24 से अधिक पुलिसकर्मी, कई ग्रामीण भी घायल होने की सूचना
नुकसान	कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त, आग लगाने के प्रयास की जानकारी
सड़क व्यवस्था	अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग प्रभावित
पुलिस का दावा	आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई थी टीम
ग्रामीणों का दावा	भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुआ विवाद
वर्तमान स्थिति	भारी पुलिस बल तैनात, जांच जारी

स्वास्थ्य मंत्री से मिले शिक्षक,लंबित मांगों के समाधान का मिला भरोसा

टीईटी विसंगति,पुरानी पेंशन,पदोन्नति और अवकाश सहित कई मुद्दों पर शासन स्तर पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, जिला एमसीबी के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सौजन्य मुलाकात कर शिक्षकों की वर्षों से लंबित विभिन्न समस्याओं और मांगों को विस्तार पूर्वक उनके समक्ष रखा, प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए शासन स्तर पर प्रभावी पहल करने का आग्रह किया।

टीईटी विसंगति,पुरानी पेंशन और पदोन्नति प्रमुख मुद्दे-प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपे ज्ञापन में प्रमुख रूप से टीईटी संबंधी विसंगतियों के निराकरण, पुरानी पेंशन योजना के लिए पूर्व सेवा अवधि की गणना तथा जिला शिक्षा कार्यालय में लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को आगामी 15 अगस्त से पहले पूरा कराने की मांग उठाई, संगठन का कहना था कि इन मुद्दों के लंबित रहने से बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हैं और उनमें असंतोष बढ़ रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने शिक्षा मंत्री से की तत्काल चर्चा-मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तत्काल दूरभाष पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से चर्चा की, उन्होंने टीईटी संबंधी विसंगतियों और पुरानी पेंशन योजना में पूर्व सेवा अवधि की गणना जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी देते हुए शीघ्र समाधान का अनुरोध किया, इसके साथ ही उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) से भी फोन पर चर्चा कर लंबित पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर इसे पूरा करने के निर्देश दिए, मंत्री ने लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) के अधिकारियों से भी संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

शिक्षकों को दिया सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा-स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शिक्षकों की मांगें महत्वपूर्ण हैं और राज्य सरकार इनके समाधान के प्रति गंभीर एवं संवेदनशील है, उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

संवाद जारी रखने की बात-छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि संगठन भविष्य में भी शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन-प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से अपनी बात रखता रहेगा,आवश्यकता पड़ने पर व्यापक स्तर पर संवाद और सकारात्मक प्रयास जारी रखे जाएंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी को भी सौंपा अलग ज्ञापन

स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी से भी भेंट कर जिला स्तर की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की, इस दौरान डीईओ को सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखी गई अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को 20 आकस्मिक अवकाश (सीएल) का लाभ दिया जाए,जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को अर्जित अवकाश प्रदान किया जाए, लोकसभा निर्वाचन कार्य में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाए,लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए।

शिक्षकों ने कहा...समयबद्ध समाधान से बढ़ेगा मनोबल

प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाता है तो शिक्षकों को लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक समस्याओं से राहत मिलेगी, इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और शिक्षा व्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, संगठन ने उम्मीद जताई कि शासन एवं प्रशासन शिक्षकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए इन मांगों पर जल्द ठोस निर्णय लेगा।

जिला प्रशासन और निकोन छत्तीसगढ़ की संयुक्त पहल,

दो दिवसीय फोटोग्राफी कार्यशाला संपन्न,विद्यार्थियों ने सीखी आधुनिक कैमरा तकनीक और वीडियोग्राफी की बारीकियां

-संवाददाता-

सूरजपुर,24 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। डिजिटल युग में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को तकनीकी एवं रोजगारपरक कौशल से जोड़ने के उद्देश्य से जिला प्रशासन सूरजपुर एवं निकोन छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय फोटोग्राफी कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन हुआ, जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न स्कूलों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया,कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक कैमरा तकनीक, डिजिटल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के क्षेत्र में व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना था, ताकि वे इस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से परिचित हो सकें।

कैमरा तकनीक से लेकर कंपोजिशन तक मिला प्रशिक्षण-कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को आधुनिक कैमरों की कार्यप्रणाली, विभिन्न प्रकार के लेंस, उनके उपयोग, कैमरा संचालन, फ्रेमिंग, कंपोजिशन, प्रकाश व्यवस्था तथा प्रभावी फोटोग्राफी के मूलभूत सिद्धांतों की विस्तार से जानकारी दी, साथ ही यह भी बताया गया कि

किसी दृश्य को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए तकनीकी समझ के साथ रचनात्मक दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण होता है।

इनका रहा महत्वपूर्ण योगदान-कार्यशाला के सफल आयोजन में डीएमसी मनोज कुमार साहू, पर्यटन विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. मोहन लाल साहू,प्रभारी प्राचार्य बृजलाल साहू,सहायक प्राध्यापक अनिल चक्रधारी, निकोन टीम के गौरव जैन एवं अनुग्रह पुरोहित, प्रशिक्षक मोहित साहू तथा विभिन्न विद्यालयों के नोडल शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

जब बारिश में 15 साल की श्रीदेवी ने किया 55 साल के एक्टर से रोमांस,

भारी बवाल के बीच हिट हुआ था यह कल्ट गाना

दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी ने महज 15 साल की उम्र में 55 वर्षीय एक्टर के साथ एक गाने में रोमांस किया था। इस उम्र के अंतर पर विवाद के बावजूद,यह गाना और फिल्म सुपरहिट हुई। भारतीय सिनेमा में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं, जिन्होंने खूब सफलता पाई। कुछ मुकाम तो ऐसे हासिल किए,जिन्हें तोड़ना शायद ही मुश्किल है और ऐसा ही नाम दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी का था। श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ सिनेमा तक कई भाषाओं में काम किया,लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीदेवी ने महज 15 साल की उम्र में अपने से लगभग तीन गुना ज्यादा उम्र वाले एक्टर के साथ रोमांस किया था।

जब 55 साल के हीरो से 15 की श्रीदेवी ने किया रोमांस

श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरूआत बेहद बचपन से ही कर दी थी। उन्होंने अपने करियर में काम करना साउथ फिल्मों से शुरू किया था। इसके बाद धीरे-धीरे कहानी हिंदी फिल्मों तक आई और फिर उन्होंने वो किया, जो आजतक कोई नहीं कर पाया। हालांकि हिंदी फिल्मों में आने से पहले श्रीदेवी ने साउथ के सुपरस्टार एनटी रामाराव के साथ रोमांस किया था। जी हां, जब श्रीदेवी ने एनटी रामा राव के साथ रोमांस किया तब वह महज 15 साल की थीं और उस वक्त एनटीआर की उम्र 55 साल की थी। मतलब करीब 40 साल बड़े हीरो के साथ श्रीदेवी ने एक गाने की शूटिंग की थी।

कौन सी है वह फिल्म?

श्रीदेवी ने एनटीआर के साथ जिस फिल्म में काम किया था असल में वह 1979 में आई तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म वेटागाडु है। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ एनटीआर थे। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म के एक गाने को लेकर हुई थी, जिसमें श्रीदेवी ने 55 साल के एनटीआर के साथ एक गाने में रोमांस किया था। हैरानी की बात तो यह है कि, इस फिल्म में केवल 8-9 साल की श्रीदेवी ने एनटीआर के पोती का किरदार निभाया था। साल 1972 में आई फिल्म बडी पंथुलु में श्रीदेवी एनटीआर की पोती के किरदार में थीं और महज कुछ सालों के भीतर ही उन्होंने उनकी प्रेमिका का किरदार भी निभाया। हालांकि यह देखने और सुनने में काफी अजीब था,पर उस दौर में इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई,हालांकि सवाल जरूर उठे थे। भले ही फिल्म को लेकर विवाद हुए, लेकिन फिल्म हिट हुई,गाने हिट हुए और इसके बाद श्रीदेवी साउथ की बड़ी एक्ट्रेस बन गईं और फिर यहीं से हिंदी सिनेमा के लिए उनके द्वार खुले।

हैंगओवर से ट्रेन के रोमांस तक

12 साल बाद भी दिलों पर राज कर रही है,सलमान-जैकलीन की किक वाली केमिस्ट्री

सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिज की किक वाली केमिस्ट्री 12 साल बाद भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। जैसे ही किक ने 12 शानदार साल पूरे किए हैं, यह सलमान खान और जैकलीन फर्नांडीज के बीच की उस यादगार केमिस्ट्री को फिर से देखने का सही समय है जिसने फिल्म को उसका दिल दिया। हालांकि किक जबरदस्त एक्शन और जबरदस्त एंटरटेनमेंट से भरी थी,लेकिन देवी और शायना के बीच हल्के-फुल्के,मजेदार और इमोशनल पलों ने दर्शकों को सच में जोड़ा।

जब नहीं रुकी जैकलीन की हंसी

कभी-कभी,सबसे यादगार पल सबसे नेचुरल होते हैं। जब सलमान खान की देवी अपनी अलग जिंदगी की सोच शेयर करती हैं,तो जैकलीन जोर-जोर से हंसने लगती हैं,और अपने कैरेक्टर में नहीं रह पातीं। उनकी सच्ची हंसी और उनके साथ की सहज दोस्ती ने इस सीन को एकदम असली बना दिया,और फैंस आज भी इसकी गर्मजोशी और चार्म के लिए इसे दोबारा देखते हैं।

मंदिर तक गाड़ी की सवारी

सिंपल लेकिन जादुई, यह सीन फिल्म के सबसे प्यारे पलों में से एक है। जब देवी और शायना एक साथ बैलगाड़ी पर मंदिर की ओर जाते हैं,

तो कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं होतीं, बस मजेदार बातें होती हैं, एक-दूसरे को देर तक देखती रहती हैं, और एक अनकहा रिश्ता जो चुपचाप पनपता है। सलमान और जैकलीन साबित करते हैं कि कभी-कभी सबसे आसान सीन भी सबसे गहरा असर डालते हैं।

रीयूनियन

फिल्म के सबसे इमोशनल सीन में से एक तब आता है जब शायना एक बार फिर देवी से

मिलती है। लेकिन इस बार, वह उसे न पहचानने का नाटक करता है। जैकलीन ने शाइना के कन्फ्यूजन और दिल टूटने को खूबसूरती से दिखाया है,जबकि सलमान ने मिस्ट्री और कंट्रोल को बैलेंस किया है, जिससे पुरानी यादों, टेंशन और अनसुलझे इमोशंस से भरा एक रीयूनियन बनता है।

हैंगओवर

हैंगओवर सिर्फ फिल्म के सबसे पसंदीदा गानों में से एक नहीं था, बल्कि यह ऑडियंस के लिए एक इमोशन बन गया। हल्की मुस्कान,मतलब भरी नजरों और आसान एक्सप्रेशन के ज़रिए, सलमान और जैकलीन ने एक ऐसा रोमांस दिखाया जो कोमल, चंचल और सच्चा लगा। उनकी केमिस्ट्री ने हर फ्रेम को ऊंचा किया, जिससे यह गाना आज भी यादगार बन गया है।

द ट्रेन मीट-क्यूट - व्हेयर इट ऑल बिगन

हर यादगार लव स्टोरी को एक यादगार पहली मुलाकात की जरूरत होती है,और किक ने ठीक वैसा ही किया। ट्रेन में उनकी अचानक हुई मुलाकात ने सलमान खान के आसान करिश्मे और जैकलीन फर्नांडीज के खूबसूरत चार्म को पूरी तरह से दिखाया। उनकी चंचल नोकझोंक और तुरंत हुई चिंगारी ने फिल्म की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक की नींव रखी।बारह साल बाद भी,किक कई पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन कर रही है,और सलमान खान और जैकलीन फर्नांडीज के बीच की केमिस्ट्री इसकी सबसे यादगार हाइलाइट्स में से एक है। हंसी और रोमांस से लेकर दिल को छू लेने वाले रीयूनियन तक,ये यादगार पल फैंस को याद दिलाते रहते हैं कि इतने सालों बाद भी किक एक पसंदीदा ब्लॉकबस्टर क्यों बनी हुई है।

वेलकम टू द जंगल के सेट पर एक साथ इतनी वैनिटी वैन देख तुषार के उड़े थे होश

तुषार कपूर ने वेलकम टू द जंगल के सेट पर वैनिटी वैन और एंटरेज कल्चर पर हुए भारी खर्चों पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने एक्टर्स की टेंशन के बारे में भी बताया। 26 जून को अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। इस फिल्म को दर्शकों का बेहद शानदार रिस्पॉन्स मिला। मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 133 करोड़ और दुनियाभर में लगभग 187 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की।

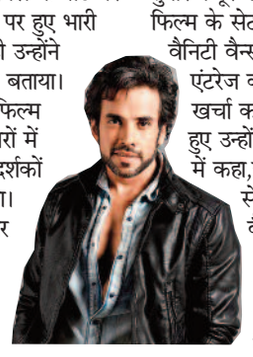

फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 28 दिन पूरे हो चुके हैं। अब हाल ही में फिल्म में अक्षय कुमार के मैनेजर का रोल अदा करने वाले अभिनेता तुषार कपूर ने फिल्म के सेट पर वैनिटी वैन्स और स्टार्स के एंटरेज कल्चर पर किए गए भारी खर्चों को लेकर सवाल उठाया है।

एक साथ 50 वैनिटी वैन देखकर हैरान रह गए थे तुषार

तुषार कपूर ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म के सेट पर तकरीबन 50 के आसपास वैनिटी वैन्स खड़ी रहती थीं। बॉलीवुड के एंटरेज कल्चर और जरूरत से ज्यादा खर्चा करने के चलन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने स्क्रीन से एक खास बातचीत में कहा,जब मैं वेलकम टू द जंगल के सेट पर पहुंचता था,तो मुझे अपनी वैनिटी वैन तक पहुंचने में ही पांच मिनट लग जाते थे,क्योंकि वहां वैनिटी वैन्स की इतनी लंबी लाइन लगी होती थी। मैं उन्हें देखता था और सोचता था कि वैन्स और स्टाफ पर कितना ज्यादा खर्च आता होगा। क्या इतने सारे एक्टर्स को एक साथ लेना जायज है? मैं सोचता था कि निर्देशक अहमद खान का विजन क्या होगा? वह एक नया जॉनर लेकर आए हैं, जिसे अभी तक किसी ने भी इंडिया में बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इतने एक्टर्स को लेना और इतने सारे पैसे खर्च करना क्या जस्टिफाइड है।

जब राज कुमार ने गोविंदा के गिफ्ट को बना दिया रुमाल

बॉलीवुड में कई सितारों की अपनी अलग पहचान रही है। कुछ कलाकार अपने शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपने अंदाज,फैशन और व्यवहार के लिए। 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा अपनी मस्ती भरी अदाओं, बेहतरीन डांस और रंग-बिरंगे फैशन स्टाइल के लिए मशहूर रहे हैं। वहीं दिग्गज अभिनेता राज कुमार अपने दमदार व्यक्तित्व, गंभीर अंदाज और बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते थे। दोनों कलाकारों का स्वभाव एक-दूसरे से काफी अलग था। अब दोनों से जुड़ा एक पुराना किस्सा सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें गोविंदा और राज कुमार के बीच का दिलचस्प पल सामने आया है। फिल्ममेकर मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान इस किस्से का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि एक बार गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बेहद आकर्षक और अलग डिजाइन की शर्ट पहनकर सेट पर पहुंचे थे। उनका यह स्टाइल हमेशा की तरह काफी अलग और ध्यान खींचने वाला था। उस दौरान राज कुमार की नजर गोविंदा की शर्ट पर पड़ी और उन्हें वह पसंद आ गई। मेहुल कुमार के मुताबिक, राज कुमार ने गोविंदा की शर्ट की तारीफ की थी,लेकिन उनका अंदाज थोड़ा अलग था। गोविंदा इस तारीफ को पूरी तरह समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि अगर राज कुमार को यह शर्ट पसंद आई है तो क्यों न उन्हें भी ऐसी ही शर्ट गिफ्ट की जाए। इसके बाद गोविंदा ने अगले दिन वैसी ही एक शर्ट खरीदकर राज कुमार को तोहफे में दे दी। हालांकि इसके बाद जो हुआ,उसने गोविंदा को हैरान कर दिया। मेहुल कुमार ने बताया कि राज कुमार ने उस शर्ट को पहनने के बजाय उससे अपने हाथ पोंछ लिए और यहां तक कि अपनी नाक भी साफ कर ली। गोविंदा यह देखकर चौंक गए थे। यह घटना राज कुमार के अपने अनोखे अंदाज को दर्शाती है, जिसके लिए वह इंडस्ट्री में अलग पहचान रखते थे। मेहुल कुमार ने बातचीत के दौरान राज कुमार और गोविंदा से जुड़ा एक और किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि राज कुमार अक्सर गोविंदा के मस्ती भरे अंदाज को लेकर मजाक किया करते थे। एक बार उन्होंने मेहुल कुमार से कहा था कि गोविंदा हमेशा नाचते ही रहते हैं। इस बात पर मेहुल कुमार हंस पड़े और उन्होंने कहा कि गोविंदा एक शानदार डांसर हैं। इसके बाद राज कुमार ने अपने खास अंदाज में सवाल किया कि अगर वह डांसर हैं तो सेट पर भी हर समय डांस क्यों करते रहते हैं। हालांकि मेहुल कुमार ने बताया कि राज कुमार ने यह बात कभी सीधे गोविंदा से नहीं कही थी। गोविंदा और राज कुमार दोनों ही हिंदी सिनेमा के यादगार कलाकार रहे हैं। जहां गोविंदा ने अपनी कॉमेडी, डांस और चुलबुले अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज किया, वहीं राज कुमार ने अपनी भारी आवाज,संवाद अदायगी और दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच अलग मुकाम बनाया। दोनों की यह कहानी बॉलीवुड के उन किस्सों में शामिल है,जो आज भी फैंस को काफी पसंद आते हैं।

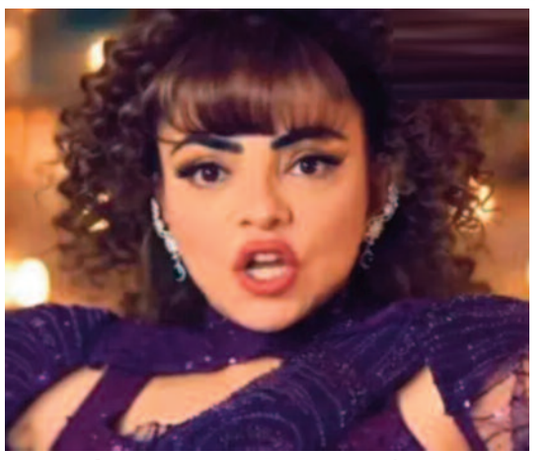

चुड़ैल बनीं राखी विजन बोलीं...

अबला नारी वाले रोल मुझसे नहीं होते

हम पांच और देख भाई देख जैसे लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों से दर्शकों को हंसाने वाली मशहूर अभिनेत्री राखी विजन एक बार फिर छोटे पर्दे पर धमाकेदार वापसी कर रही हैं। इस बार वह किसी सीधी-साधी लड़की के रूप में नहीं,बल्कि चुड़ैल के अनोखे और दिलचस्प किरदार में नजर आ रही हैं। सोनी सब पर प्रसारित होने वाले नए धारावाहिक चुड़ैल चली ससुराल में राखी कामिनी नाम की चुड़ैल की भूमिका निभा रही हैं, जो सीबीआई यानी चुड़ैल ब्लड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष है। अपने इस नए अवतार और करियर को लेकर बात करते हुए राखी विजन ने कहा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में हम पांच में स्वीटी जैसी बेहद मासूम और भोली-भाली लड़की का किरदार निभाया था। तब लोगों ने उनके काम की खूब सराहना की थी और उसे उनके लिए परफेक्ट रोल बताया था। अब उम्र के इस पड़ाव पर जब वह एक चुड़ैल की भूमिका निभा रही हैं,तब भी लोग उनके अभिनय की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यह नया शो पूरी तरह से डरावना नहीं है, बल्कि इसमें हॉरर के साथ-साथ भरपूर कॉमेडी का तड़का भी लगाया गया है।

खेल समाचार

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में 5 खिलाड़ी दे सकते हैं बड़ा उलटफेर

नई दिल्ली,24 जुलाई 2026। हर बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में कुछ अविस्मरणीय उलटफेर देखने को मिलते हैं। हालांकि अक्सर बड़े नाम सुर्खियों में छाए रहते हैं,लेकिन इतिहास गवाह है कि युवा खिलाड़ी भी मौके का फायदा उठाकर एक ही सप्ताह में अपना करियर बदल सकते हैं। नई दिल्ली 17 से 23 अगस्त तक बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है, और खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी खेल के सबसे बड़े सितारों के खिलाफ खुद को आजमाने के लिए उत्सुकता से पहुंचेगी। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार,यहां पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास प्रतिभा और फॉर्म दोनों हैं और वे बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप इंडिया 2026 में उलटफेर कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली,24 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित होने वाले कॉमन वेल्थ गेम्स 2026 में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय दल खेलों के इस बड़े मंच पर पूरे जोश,आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ प्रदर्शन करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। प्रधानमंत्री ने भारतीय दल को शुभकामना संदेश देते हुए कहा कि खिलाड़ियों में कड़ी मेहनत,अनुशासन और जीत का जज्बा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और समर्पण के बल पर शानदार प्रदर्शन करेंगे।

एनसिनो की धमाकेदार जीत एटॉमिक प्रिंस प्लेट पर कब्जा

पुणे,24 जुलाई 2026। पुणे रेस कोर्स में शुक्रवार को आयोजित पुणे रेसिंग सीज़न के दूसरे दिन के मुख्य आकर्षण 'एटॉमिक प्रिंस प्लेट' में चार साल के घोड़े एनसिनो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। अधिराज एस. जोधा द्वारा प्रशिक्षित एनसिनो ने अपनी पहली पुणे रेस में ही प्रभावशाली शुरुआत की और अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। जॉकी ए. संदेश की शानदार राइडिंग के दम पर एनसिनो ने छह-फर्लांग लंबी इस रेस में अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया। उसने 'फाइटॉन' को पांच से अधिक लेंथ के अंतर से हराकर आसान जीत दर्ज की। रेस के दौरान एनसिनो ने शुरुआत से ही संतुलित और नियंत्रित प्रदर्शन किया। घोड़े ने पूरे ट्रैक पर अपनी गति और ऊर्जा को बनाए रखा और सही समय का इंतजार किया। होम स्ट्रेट में पहुंचने के बाद एनसिनो ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते बाकी घोड़ों से आगे निकल गया। उसके इस शानदार प्रदर्शन के बाद अन्य सात घोड़ों के लिए उसे पकड़ पाना मुश्किल हो गया।

एशियन गेम्स में फिर दिखेगा भारत-पाक का रोमांच

सेमीफाइनल या फाइनल में हो सकती है महाटक्कर

नई दिल्ली,24 जुलाई 2026। जापान में आयोजित होने वाले आगामी एशियाई खेलों में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक खबर सामने आई है। मौजूदा चैंपियन भारत और चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की पुरुष एवं महिला क्रिकेट टीमों को प्रतियोगिता में सीधे क्वार्टर फाइनल चरण में प्रवेश (सीधा प्रवेश) दिया गया है। एशियाई खेलों के क्रिकेट शेड्यूल और ड्रॉ के अनुसार, नॉकआउट मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज भिड़ंत देखने को मिल सकती है।

पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में जहाँ सेमीफाइनल में ही भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हो सकती हैं,वहीं महिला वर्ग के समीकरणों के अनुसार दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला (फाइनल) होने की पूरी संभावना बन रही है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। भारतीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच से करेगी। सेमीफाइनल में भारतीय महिलाओं का मुकाबला बांग्लादेश या चीन में से किसी एक टीम से होने के आसार हैं। दूसरी ओर, पुरुषों की क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर को फाइनल मुकाबले के साथ समाप्त होगी। पुरुष वर्ग में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रारंभिक चरण के लिए टीमों को दो समूहों में बाँटा गया है–ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में हांगकांग,चीन,मलेशिया और ओमान को रखा गया है। भारत और पाकिस्तान सहित शीर्ष रैंक वाली टीमों को सीधे नॉकआउट (क्वार्टर फाइनल) दौर में स्थान दिया गया है। एशियाई खेलों में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जापान के आइची प्रांत स्थित कोरोजी एथलेटिक पार्क में टी-20 प्रारूप में किया जाएगा। भारतीय पुरुष टीम की कमान स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी,जबकि महिला टीम की अगुवाई अनुभवी कप्तान हरमनप्रीत कौर करेंगी। गौरतलब है कि एशियाई खेलों के इतिहास में क्रिकेट चौथी बार आधिकारिक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले क्रिकेट को 2010 (ग्वांगझू), 2014 (इंचियोन) और 2023 (हांगझोऊ) एशियाई खेलों में भी शामिल किया जा चुका है।

न्यायालय नायब तहसीलदार भैयाथान,जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा.प्र.क्र. /ब/121 वर्ष
ग्राम -कुसमुसी पह0न0-11

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजकुमार पिता अलीराम जाति कंवर निवासी ग्राम कुसमुसी पह0न0-11 रा0नि0म0 भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्री उर्मिला पैकरा आ. राजकुमार का जन्म दिनांक 02/03/2008 को ग्राम कुसमुसी मे हुई है अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है आवेदक अपने पुत्री उर्मिला पैकरा का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कुसमुसी को आदेशित करने आवेदन पेश किया है जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 28/07/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते है नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार किया जावेगा ।

आज दिनाँक 08/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

सील कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भैयाथान,जिला-सूरजपुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र.202607021700032
/ ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामलाल आ0 स्व0 देवसाय, निवासी ग्राम भगवानपुरखुर्द,तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम भगवानपुरखुर्द स्थित भूमि खसरा नंबर 155 / 1 रकबा 0.210 हे0 में से 30 डिसमिल भूमि मकान मरम्मत एवं परिवार के जीवन यापन हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण अनावेदक विश्वजीत मण्डल आ0 अशोक मण्डल, निवासी सुभाषनगर, भगवानपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) को रू0 5,28,000/- (पांच लाख अट्ठाईस हजार रूपये) में विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 19/08/2026 से पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 23/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-02

नाम परिवर्तन सूचना

अर्जुन राम पुराना नाम, जिसे बदला जाना है सुपुत्र विरेन्द्रसिंह निवासी जजावल तहसील प्रतापपुर जिला- सूरजपुर छ0ग0 का स्थायी निवासी हूँ। मेरा पूराना नाम बिरेन्द्र सिंह है और मै अपना नाम बदलकर बिरेन्द्र सिंह नया नाम विरेन्द्र कुमार रजक करवाना चाहता हूँ। मेरे पुराने नाम से किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है और न ही किसी बैंक में ऋण की राशि शेष है। मैं अपना नाम बदलकर यदि कोई गैर कानूनी काम करता हूँ तो उसके लिए में पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार रहूंगा । मेरा शपथ पत्र अपने पूरे होशोहवास में रहकर हस्ताक्षर कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

शपथग्रहिता
अर्जुन राम (पुराना नाम)

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मैं विश्वनाथ (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र / सुपुत्री जतन साय गाँव/शहर भाठापारा, ग्राम सलका, पोस्ट - लहपटरा, तहसील लखनपुर, जिला- सरगुजा,छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र / सुपुत्री का नाम सुषमावती (SUSHMAVATI) (पुराना नाम) से बदल कर अमिता (AMITA) (नया नाम) रख लिया हैं। मेरी पुत्री का आधार कार्ड में जन्मतिथि 02.09.2010 अंकित है जो त्रुटिपुर्ण है, सही जन्मतिथि 09.08.2010 हैं ।

पालक
विश्वनाथ
भाठा पारा,ग्राम सलका,पोस्ट - लहपटरा,लखनपुर,सरगुजा,छ0ग0

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मैं रामचन्द्र केंवट (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री बालदेव केंवट गॉव / शहर महादेव पारा खास, ग्राम अमलभिट्ठी, पोस्ट -तुरना,तहसील लखनपुर, जिला - सरगुजा, छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम हिमालय (HIMALAY) (पुराना नाम) से बदल कर हिमांशु केंवट (HIMANSHU KENVAT) (नया नाम) रख लिया हैं।

पालक
रामचन्द्र केंवट
महादेव पारा खास,ग्रा.अमलभिट्ठी पो.तुरना,लखनपुर,सरगुजा,छ0ग0

यूसीसी लागू होने पर छत्तीसगढ़ देश का पांचवां राज्य बनेगा

सीएम साय बोले...आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी बिल पास कराएंगे...

रायपुर,24 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य कैबिनेट पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक को विधानसभा से पारित कराएगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक हुई। इसके साथ ही यूसीसी का प्रारूप तैयार करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड,गुजरात,असम और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। विधेयक पारित होकर कानून लागू होने पर यह देश का पांचवां राज्य बन जाएगा।

समिति पूरे राज्य से लेगी सुझाव

समिति राज्य के सामाजिक और अन्य पहलुओं का अध्ययन करेगी। अलग-अलग वर्गों और हितधारकों से सुझाव भी लिए जाएंगे। इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

यूसीसी को लेकर अब तक क्या-क्या हुआ?

- **15 अप्रैल 2026 :** राज्य कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- **26 जून 2026 :** सरकार ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी।
- **24 जुलाई 2026 :** समिति की पहली बैठक के साथ मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड : यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे नागरिक कानूनों में एकरूपता आएगी, न्याय प्रक्रिया सरल होगी और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में खुलेगा सत्य साईं ट्रस्ट का अस्पताल : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 700 करोड़ से अधिक सरचार्ज माफ

रायपुर,24 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेंगलुरु दौरे से वापस रायपुर लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने बेंगलुरु प्रवास और प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना को लेकर जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे सत्य साई ट्रस्ट के सदुरु मधुसूदन साई के 47वें जन्मोत्सव समारोह में शामिल होने बेंगलुरु गए थे। सत्य साई ट्रस्ट का छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा अस्पताल संचालित हो रहा है, जहां 15 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के हृदय रोग का निःशुल्क इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की ओर से आने वाले समय में प्रदेश में और भी अस्पताल खोले जाने की योजना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना को लेकर कहा कि प्रदेश में लोगों के बिजली बिल लंबे समय से पेंडिंग होने की शिकायतें सामने आती थीं। कोरोना काल के दौरान भी कई लोगों के बिजली बिल लंबित हो गए थे। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। साय ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल अधिक बढ़ गया है, उन्हें संबंधित बिजली कार्यालय में पंजीयन कराना है। अब तक 42 हजार से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और यह संख्या आगे और बढ़ने की संभावना है। सीएम साय के मुताबिक, योजना के तहत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 700 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली सरचार्ज माफ किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य आम लोगों को बिजली बिल के बढ़े हुए भार से राहत देना और लंबित बिलों के समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है।

अतिथि शिक्षकों की हड़ताल खत्म...सरकार से आश्वासन के बाद लिया फैसला,मांगें पूरी नहीं होने पर फिर सड़क पर उरतने की दी चेतावनी

दुर्ग,24 जुलाई 2026। 23 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अतिथि शिक्षकों ने आखिरकार अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से मिले सकारात्मक आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित किया गया है। हालांकि अतिथि शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 5 सितंबर 2026 तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे एक बार फिर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। दुर्ग में प्रेसवार्ता कर अतिथि शिक्षक संघ ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की। शिक्षकों ने कहा कि वे आंदोलन नहीं करना चाहते थे, लेकिन 2016 से मिल रहा मानदेय आज की महंगाई के दौर में उनके लिए बेहद कम है। उनका कहना है कि कई शिक्षक 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर और नक्सल प्रभावित इलाकों में जान जोखिम में डालकर बच्चों को पढ़ाने पहुंचते हैं। अतिथि शिक्षकों का दावा है कि उनके प्रयासों से दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियमित शिक्षकों की तुलना में बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है। नियमित शिक्षकों को करीब एक लाख रुपये और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों को 38 हजार रुपये तक मिलते हैं, जबकि अतिथि शिक्षकों को महज 20 हजार रुपये दिए जाते हैं। शिक्षकों ने मातृत्व अवकाश, सामान्य छुट्टियों और पूरे 12 महीने के वेतन की मांग भी उठाई। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि 12 महीने काम लेने के बावजूद उन्हें केवल साढ़े दस महीने का मानदेय दिया जाता है।सरकार की ओर से वेतन वृद्धि, 13 सीएल, 12 महीने का मानदेय और भविष्य में नियमितीकरण को लेकर संकेत मिलने के बाद शिक्षकों ने फिलहाल आंदोलन स्थगित किया है। हालांकि पुलिस कार्रवाई और कथित बदसलूकी को लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जताई।

महादेव सट्टा केस, विकास गर्ग की न्यायिक रिमांड बढ़ी

सट्टे के पैसे से खरीदी 1200 करोड़ की कंपनी,पैसे घुमाने वाले रसूखदारों से ईडी करेगी पूछताछ

रायपुर,24 जुलाई 2026। महादेव ऑनलाइन सट्टा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में EBIX कंपनी के मालिक विकास गर्ग को 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद विशेष अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। ईडी का दावा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां और दस्तावेज मिले हैं,जिनके आधार पर जांच का दायरा और बढ़ सकता है।

10 दिन तक अफसरों ने की पूछताछ

ईडी के मुताबिक,विकास गर्ग से 10 दिनों तक वित्तीय लेनदेन,बैंक खातों और कथित अवैध धन के इस्तेमाल को लेकर गहन पूछताछ की गई। एजेंसी का कहना है कि पूछताछ में ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों और मनी ट्रेल को समझने में मदद मिलेगी। जांच एजेंसी का आरोप है कि

विकास गर्ग के महादेव ऐप के प्रमुख आरोपियों में शामिल सौरभ चंद्राकर से कारोबार और आर्थिक संबंध रहे हैं। ईडी के अनुसार, जांच के दौरान दोनों के बीच हुए वित्तीय लेनदेन और कारोबारी संपर्कों से जुड़े कई दस्तावेज सामने आए हैं। इसके अलावा सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और उनके परिवार से जुड़े बैंक खातों में रकम जमा किए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी एजेंसी को मिली हैं।

1,175 करोड़ रुपए में अमेरिकी कंपनी खरीदी : ईडी पहले ही आरोप लगा चुकी है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म से अर्जित अवैध कमाई को विभिन्न कंपनियों और वित्तीय माध्यमों के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की गई। जांच में बैंक ट्रांजेक्शन, वित्तीय दस्तावेज और निवेश से जुड़े कई रिकॉर्ड एजेंसी के कब्जे में आए हैं। सूत्रों के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया है कि सट्टे से अर्जित धन का इस्तेमाल विदेशों में निवेश और करीब 1,175 करोड़ रुपए में अमेरिकी कंपनी को खरीदे जाने के आरोपों की भी जांच की जा रही है।

सिंडिकेट से जुड़े रसूखदारों से होगी पूछताछ

ईडी का कहना है कि विकास गर्ग से मिली जानकारी के आधार पर अब अन्य संदिग्धों की भूमिका, बैंक खातों और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की गहन जांच की जाएगी। एजेंसी आने वाले दिनों में इस मामले में और लोगों से पूछताछ तथा नई कार्रवाई कर सकती है। महादेव ऑनलाइन सट्टा केस पहले से ही देश के सबसे चर्चित आर्थिक अपराध मामलों में शामिल है और इसकी जांच लगातार विस्तार ले रही है।

पति ने मांगा तलाक,पत्नी ने की 2-करोड़ की डिमांड

हाईकोर्ट बोला...मानसिक क्रूरता,ऐसी मांग से रिश्ता बचना मुश्किल,महिला की अपील खारिज

बिलासपुर,24 जुलाई 2026। शादी के करीब 2 साल बाद पति-पत्नी के रिश्ते में दरार आ गई। तलाक के मामले में मध्यस्थता के दौरान पत्नी ने स्थायी भरण-पोषण के लिए पति से 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस अत्यधिक मांग को पति के प्रति मानसिक क्रूरता माना है। साथ ही पत्नी की याचिका खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें महिला के लिए 10 लाख रुपए का स्थायी भरण-पोषण तय किया गया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि जब अत्यधिक और असामान्य आर्थिक मांग के कारण मध्यस्थता विफल हो जाती है, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि रिश्ता उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी संभव नहीं है। ऐसे हालात में शादी को जबरन बनाए रखने का दबाव बनाना पति पर मानसिक क्रूरता के समान है। दरअसल, रायपुर निवासी दंपती की शादी 29 जून 2020 को हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। पति का आरोप था कि पत्नी 7 फरवरी 2022 को अपने भाई की शादी का बहाना बनाकर मायके गई और करीब 35 लाख रुपए मूल्य के पुश्तैनी जेवर व अन्य कीमती सामान साथ ले गई। इसके बाद महिला थाना और सखी सेंटर में हुई काउंसलिंग के बावजूद उसने वापस लौटने से इनकार कर दिया। इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की अर्जी लगाई।

फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील : फैमिली कोर्ट ने पति की आय और पत्नी की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए 10 लाख रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता तय किया था। इस फैसले के खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इसमें उसने गुजारा भत्ता बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए देने की मांग की।

2 करोड़ रुपए की मांग बनी सुलह में रोड़ा : हाईकोर्ट ने 18 जून 2026 को दोनों पक्षों को आपसी सहमति से स्थायी गुजारा भत्ते की राशि तय करने के लिए मध्यस्थता केंद्र भेजा था। सुनवाई के दौरान सामने आया कि मध्यस्थता के दौरान पत्नी ने एकमुश्त 2 करोड़ रुपए की मांग रखी। पति ने अपनी वित्तीय स्थिति और व्यावसायिक खातों का ब्योरा देते हुए इस राशि को अत्यधिक बताया और इसे देने में असमर्थता जताई, इसके कारण दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो सका।

बिजली बिल नहीं चुकाने पर छत्तीसगढ़ के 10 हजार सरकारी कनेक्शन काटे गए,51 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया था

रायपुर,24 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बढ़ते बिजली बिल बकाये को देखते हुए बिजली कंपनी ने सख्त कदम उठाते हुए 10 हजार से अधिक सरकारी बिजली कनेक्शनों को स्थायी रूप से काट दिए हैं। इसके अलावा, 1 अगस्त से सभी सरकारी कार्यालयों में प्री-पेड बिजली व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। । इन कनेक्शनों पर करीब 51 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया था। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने अपने वित्तीय प्रबंधन और बढ़ते घाटे को देखते हुए इन 10,000 सरकारी बिजली कनेक्शनों को काटने की सूची और आंकड़े जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल में ही संपन्न हुए विधानसभा के मानसून सत्र में खुद राज्य सरकार ने माना था कि विभिन्न विभागों पर 3,117 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 40 सरकारी विभागों पर कुल 3,432 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी होने से बिजली कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन पर लगातार दबाव बना हुआ है।अधिकारियों ने बताया है कि भुगतान के लिए संबंधित विभागों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन समय पर राशि जमा नहीं होने के कारण स्थायी रूप से कनेक्शन काट दिए गए । जिन सरकारी कनेक्शनों का भविष्य में दोबारा उपयोग किया जाएगा, उन्हें पुनः चालू कराने से पहले पूरा बकाया जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं जिन परिसरों में बिजली आपूर्ति अभी भी जारी है,वहां ड्यूज रिकवरी एक्ट के तहत बकाया राशि को किस्तों अथवा नियमित बिजली बिलों में समायोजित कर वसूला जाएगा। यह कार्रवाई अंबिकापुर,दुर्ग,बिलासपुर, रायपुर,जगदलपुर, महासमुंद,कोरबा,रायगढ़,जांजगीर और राजनांदगांव सहित अन्य सर्कलों में बड़ी संख्या में की गई है । रायपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर बड़े स्टार पर कनेक्शन काटे गए हैं।

छत्तीसगढ़ में 7,854 करोड़ की नई दोहरी रेल लाइन परियोजना को मिलेगी रफ्तार

रायपुर,24 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में रेल संपर्क और माल परिवहन को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई दोहरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि अप्रैल 2025 में 278 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को 7,854 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृति दी गई थी। यह रेल लाइन बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे व्यस्त रेल सेक्शनों को बाईपास करेगी, जिससे मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की आवाजाही तेज और सुगम होगी। परियोजना छत्तीसगढ़ के आठ जिलों से होकर गुजरेगी और विशेष रूप से बलौदाबाजार जिले को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। साथ ही खरसिया, जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के कोयला क्षेत्रों का प्रमुख रेल प्रवेश द्वार है, वहां से माल परिवहन को भी नई गति मिलेगी। परियोजना को 'विशेष रेलवे परियोजना' घोषित किया गया है। इसके लिए लगभग 1,852 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। रेल मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2026-27 में छत्तीसगढ़ के लिए रेलवे का बजट बढ़कर लगभग 7,470 करोड़ रुपये हो गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक आवंटन से लगभग 24 गुना अधिक है। वर्ष 2014 से 2026 के बीच राज्य में 1,311 किलोमीटर नई रेल पटरियां चालू की गई हैं। वर्तमान में राज्य में 48,202 करोड़ रुपये की लागत वाली 36 रेल परियोजनाओं पर कार्य जारी है। इनमें 8 नई रेल लाइन और 28 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं।

खम्हारडीह थाने के बाहर कांग्रेस का धरना खत्म

बैज बोले...एक हफ्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं पर होगी एफआईआर,पुलिस ने लिखित आश्वासन दिया

रायपुर,24 जुलाई 2026। रायपुर में कांग्रेस का 18 घंटे तक चला अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो गया है। दीपक बैज के मुताबिक पुलिस ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज करने का लिखित आश्वासन दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाई गई गैर-जमानती धाराओं की विवेचना की जाएगी और इसी के बाद धरना समाप्त किया गया। भाजपा-कांग्रेस बवाल के बाद कांग्रेस के 12 नेताओं और कई कार्यकर्ताओं पर दर्ज गैर-जमानती धाराओं वाली एफआईआर के विरोध में खम्हारडीह थाने के सामने यह आंदोलन किया जा रहा था। कांग्रेस की मांग थी कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी काउंटर एफआईआर दर्ज की जाए। जिन 12 कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर हुई है, वे सभी शाम को खम्हारडीह थाने पहुंचे,जहां घायल कार्यकर्ताओं का एमएलसी कराया गया। पुलिस ने गैर-जमानती धाराओं में दर्ज मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

बैठक में बनी मांगों पर सहमति

प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई नेता और कार्यकर्ता रातभर थाने के बाहर डटे रहे। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई और कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। शुक्रवार सुबह पुलिस

अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के बीच बैठक हुई। इसमें मध्य जोन डीसीपी तारकेश्वर पटेल, नॉर्थ जोन डीसीपी दीपमाला कश्यप,एडीसीपी आदित्य पांडे और एसीपी पूर्णिमा लांबा मौजूद रहे। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज,सह प्रभारी जरिता लैतफलांग,प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू,सुशील आनंद शुक्ला, सत्यनारायण शर्मा और कुलदीप जुनेजा शामिल हुए।

दीपक बैज बोले- हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं : इससे पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा था कि, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। बीजेपी की यह कार्रवाई पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित है। कांग्रेस इस कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगी।

भाजपा कुछ महीनों की मेहमान, पुलिस अधिकारी ध्यान रखें : वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सुनियोजित हमला किया गया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि, भाजपा सरकार कुछ ही महीनों की मेहमान है।

छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा..

सवारियों से भरी बस की ट्रक से जोरदार टक्कर,19 यात्री घायल,तीन गंभीर

बलौदाबाजार,24 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में यात्री बस और ट्रक की आमने-सामने की जोरदार भिडंत हो गई। हादसे में करीब 19 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही हैं। घायलों में एक ही परिवार के पांच लोग भी शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक,घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। सकरी बाइपास स्थित हाइवे पर यात्री बस की ट्रक के साथ आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद बस के अंदर चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और राहगीरों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बस के अंदर से निकाला और फोन कर तत्काल एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया। हादसे में करीब 19 यात्री घायल हो गए, जिनमें से तीन को गंभीर चोट (फ्रेक्चर) पहुंची है। बाकी घायलों को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल बलौदाबाजार में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक ही परिवार के पांच लोग भी शामिल हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक, किसी भी घायल को जान का खतरा नहीं है। सभी का उपचार जारी है। वहीं, उपचार के बाद 15 यात्रियों को छुट्टी दे दी गई है। वहीं, 4 का उपचार अभी जारी है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)